यूक्रेन पहुंचे पीएम मोदी ने एक बार फिर से शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम युद्ध से दूर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तटस्थ रहे हैं। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष शांति का है।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:253 दिनांक:24-08-2024 शनिवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया।

यूक्रेन में पीएम मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बोले इस युद्ध में हम निष्पक्ष नहीं, हमारा पक्ष शांति युद्ध से नहीं, बातचीत और कूटनीति से हल होती है समस्या

कीव(ईएमएस)। रूस और यूक्रेन में ढाई साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेता ने मैरिंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक की। इस दौरान भारत और यूक्रेन के बीच मानवीय सहायता, खेती, मेडिसिन, और कल्चरल को-ऑपरेशन बढ़ाने पर समझौता हुआ।

पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध से समस्या का समाधान नहीं होता है। बातचीत और कूटनीति से समस्या हल होती है। दोनों पक्ष आपस में बातचीत शुरू करें। बिना समय गंवाए रूस-यूक्रेन बात करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति के प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाएगा। जेलेंस्की से मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध की विभीषिका से दुख होता है। युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। उन्होंने कहा कि भारत और यूक्रेन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत और यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशमानवीय मदद, कृषि, फूड और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान भी मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत का आह्वान किया, ताकि युद्ध को शीघ्रता से समाप्त किया जा सके। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच आधिकारिक वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। इसमें भारत ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता के आदर की बात कही है। साथ ही दोनों देशों में सैन्य-तकनीक सहयोग को लेकर संयुक्त कार्य समूह की बैठक फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है।

मोदी ने स्वयं इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया। पहला कारण तो यह है कि वर्ष 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र देश बनने के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा किया है। दूसरा, मोदी ऐसे पहले वैश्विक नेता हैं, जिन्होंने कुछ ही दिनों के अंतर में रूस के साथ यूक्रेन की यात्रा की है। उन्होंने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ न सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता की, बल्कि उन्हें शांति का संदेश भी दिया है।

पोलैंड से रेल मार्ग से कीव पहुंचे पीएम मोदी का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा तनाव भरे माहौल के बावजूद शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने खास अंदाज में उन्हें गले लगाकर अभिवादन किया। दोनों नेताओं ने युद्ध में मारे गए बच्चों की स्मृति में निर्मित संग्रहालय का दौरा किया। वहां प्रदर्शित फिल्म को देख कर पीएम मोदी भावुक भी हुए।

राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा कि मैंनें और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कीव में मार्टिरोलॉजिस्ट प्रदर्शनी में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष विशेष रूप से बच्चों के लिए विनाशकारी है। इस संघर्ष में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस दुख को सहने की ताकत मिले।

पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देश मानवीय मदद, कृषि, फूड और सांस्कृतिक क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

जीएसटी स्लैब में बदलाव करने को लेकर नहीं बन पाई सहमति

- मौजूदा 4 स्लैब की व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में मंत्री समूह

नई दिल्ली (ईएमएस)। जीएसटी के कम स्लैब की मांग के दौरान विपक्ष शासित पश्चिम बंगाल और कर्नाटक समेत कई राज्य जीएसटी के मौजूदा चार स्लैब में बदलाव करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि स्लैब कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बता दें कि बीमा, ऑनलाइन गेमिंग, रेस्तरां और पेय उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए मंत्रिस्तरीय पैनल का गठन किया गया था। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी की मौजूदा 18 फीसदी की दर को कम करने की मांग को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की पहली बैठक के दौरान उठी, लेकिन इस मामले को अधिकारियों वाली फिटमेंट समिति को भेज दिया गया है, जो अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि मंत्री समूह के संयोजक हैं, ने बैठक के बाद कहा ?कि जीओएम के कुछ सदस्य मांग कर रहे हैं कि जीएसटी के तहत कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इस पर और चर्चा होगी और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जीएसटी परिषद की बैठक 9 सितंबर को होने वाली है, जिसमें दरों को तर्कसंगत बनाने का मुद्दा उठने की संभावना है। स्लैब को चार से घटाकर तीन करने पर चर्चा हुई, लेकिन इस मामले पर आम सहमति नहीं बन पाई। वर्तमान में चार मुख्य स्लैब हैं – 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने सुझाव दिया है कि स्लैब में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और जीएसटी परिषद के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा ने कहा कि जीएसटी मोटे तौर पर स्थिर हो गया है। जो चीज सुचारू रूप से चल रही है, उसमें व्यवधान क्यों डाला जाए। स्लैब को चार से घटाकर तीन करने के लिए 12 और 18 स्लैब को मिलाकर उन्हें 15-16 फीसदी के आसपास लाना होगा। इसका मतलब यह होगा कि 12 फीसदी ब्रैकेट में आने वाले उत्पाद जिसमें मक्खन, घी, कंप्यूटर, मोबाइल, छाते और 7,500 प्रति रात तक के कमरे के किराए वाले होटल आदि शामिल हैं, पर अधिक कर लगेगा। इसके अलावा सबसे कम स्लैब में दर बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, जो राजनीतिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

सेबी ने अनिल अंबानी को पांच साल के लिए शेयर बाजार से किया प्रतिबंधित

- अनिल अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया, 24 अन्य संस्थाओं पर भी लगाई रोक

मुंबई (ईएमएस)। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है और पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अनिल के अलावा रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से फंड के डायवर्जन के आरोप में कार्रवाई की है। सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को भी कंपनी से धन निकालकर डायवर्ट करने के कारण पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। अनिल अंबानी 5 साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी, या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में प्रतिभूति बाजार से नहीं जुड़ सकेंगे। रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया। इसके अलावा न रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी की ओर से 22 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा गया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से आरएचएफएल से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी, जिसे उन्होंने अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में छिपाकर रखा था। हालांकि आरएचएफएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस तरह के ऋण देने के तरीकों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे और नियमित रूप से कॉर्पोरेट लोन की जांच की थी लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया। इससे पता चलता है कि शासन में महत्वपूर्ण विफलता है, जो अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की ओर से संचालित है। रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं पर कार्रवाई की है, उनके सूची इस प्रकार है- रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड- अनिल डी. अंबानी, अमित बापना, रविंद्र सुधालकर, पिंकेश आर. शाह, आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एरियन मूवी प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डीप इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड, अजालिया डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, विनायक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, गेमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेडीबिज प्राइवेट लिमिटेड, हिरमा पावर लिमिटेड, टयूलिप एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (अब सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है), रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड, रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड।

कोलकाता रेप-मर्डर केस में आरोपी समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा

-पूर्व प्रिंसिपल और पीडित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर करने वाले आरोपी संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीडित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं।

शुक्रवार को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह की स्पेशल कोर्ट ने पेश किया। जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स शुक्रवार को 15वें दिन भी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा- हमें न्याय नहीं मिला है। इसलिए काम पर नहीं लौटेंगे। इधर, दूसरेसंगठनोंयूनाइटेडडॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी।

मथुरा में बाढ़, सडक़ें धसीं... त्रिपुरा में सेना 22 लोगों की मौत

नई दिल्ली/भोपाल(ईएमएस)। मप्र सहित देशभर में एक बार फिर मानसूनी बारिश तेज हो गई है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण देशभर में कई मौतें होने की खबर है। मप्र में बारिश के कारण कई डैम के गेट खोले जा चुके हैं। जन्माष्टमी के 3 दिन पहले मथुरा में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम को जेसीबी मशीनें लगानी पड़ीं। कई जगह सडक़ें भी धंस गईं। त्रिपुरा में पिछले 5 दिनों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 17 लाख लोग प्रभावित हैं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना ने 330 लोगों को बचाया। 65 हजार लोग 450 रिलीफ कैंप में हैं। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 80 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बलिया में गंगा और बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

त्रिपुरा में पिछले 5 दिनों में 1900 से ज्यादा लैंडस्लाइड हुई हैं। असम राइफल्स की राइफलवुमन बचाव कार्यों का नेतृत्व कर रही हैं। पूरे राज्य से अब तक 750 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी त्रिपुरा सीएम को फोन करके राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। शाह ने बताया कि एनडीआरएफ की 4 टीमें त्रिपुरा पहुंची हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुरुवार देर रात करीब 1:20 बजे लैंडस्लाइड के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू में जुटी एंडीआरएफ टीम ने सुबह चारों के शव मलबे से निकाले। इधर, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी तेज बारिश और लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। चमोली पुलिस ने बताया कि मलबा हटाने का काम जारी है।

मप्र में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। भोपाल में बीती रात से रुक रुककर बारिश हो रही है। इसके चलते केरवा डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम के चार गेट खोले गए। भोपाल के अलावा इंदौर, नर्मदापुरम और रतलाम समेत कई जिलों में गुरुवार रात से ही बारिश हो रही है। सागर में 6 साल की बच्ची नदी में बह गई। देर रात तक उसका पता नहीं चल पाया था। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्यप्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। अगले चार दिन यानी 26 अगस्त तक तेज बारिश का दौर रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ के चलते इंदौर-उज्जैन समेत 26 जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 25 अगस्त से सिस्टम और मजबूत हो जाएगा।

फिर से खुले डैम के गेट

पिछले दो-तीन दिन से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश हो रही है। इससे गुरुवार को मुरैना में पगारा डैम के 5 गेट खुल गए। वहीं, कोलार, बाणसागर, कुंडालिया, बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, कलियासोत, भदभदा, केरवा बांधों में पानी की आमद जारी है। भोपाल के बड़ा तालाब में भी पानी की बढ़ोतरी हुई है। अब लेवल 1666.50 फीट तक पहुंच गया है। 0.30 फीट पानी आते ही भदभदा डैम के गेट फिर से खुल जाएंगे। भोपाल में बीती रात से रुक-रुककर हो रही बारिश के बाद बड़ा तालाब और डैमों में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। शुक्रवार को केरवा डैम के चार गेट खोले गए।

रतलाम जिले में सुबह से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। रतलाम से 25 किलोमीटर दूर सैलाना के केदारेश्वर स्थित (सैलाना) का झरना एक बार फिर उफान पर आ गया है। केदारेश्वर कुंड का पानी मंदिर के ऊपर से बह रहा है। मप्र में अब तक करीब 80 प्रतिशत यानी 29.7 इंच पानी गिर चुका है। श्योपुर में बारिश का आंकड़ा सामान्य से दोगुना और मंडला-सिवनी में 41 इंच से अधिक है। श्योपुर में सामान्य से 145 प्रतिशत बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा बारिश के मामले में मंडला आगे है। यहां 43 इंच पानी गिर चुका है। यहां की सामान्य बारिश 47 इंच है यानी सामान्य बारिश के आंकड़े को पार करने के लिए अभी भी 4 इंच पानी की जरूरत है।

यूपी की बस नेपाल में नदी में गिरी 5 की मौत 16 गंभीर रुप से घायल

काठमांडू(ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक बस शुक्रवार को नेपाल की मास्र्यांग्डी नदी में गिर गई। इसमें 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। 14 की मौत हो गई है। इनमें एक बच्चा भी है। 31 लोग घायल हैं। इनमें 5 की हालत गंभीर है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तभी तनहुन जिले के आइना पहाड़ा में सुबह 11.30 बजे हाईवे से लगभग 500 फुट नीचे नदी में गिर गई। बस में सवार ज्यादातर यात्री महाराष्ट्र के थे। सभी नेपाल घूमने गए थे। नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल सेना सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सशस्त्र पुलिस बल के 45 जवानों की एक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। नेपाल सेना का एक एमआई-17 हेलीकॉप्टर मेडिकल टीम को लेकर काठमांडू से तनहुन के लिए उड़ान भर चुका है।

देश में पहली बार प्राइवेट कंपनी का री-यूजेबल रॉकेट शनिवार को होगा लॉन्च

नई दिल्ली(ईएमएस)। भारत का पहला निजी कंपनी का हाईब्रिड पुनः प्रयोज्य (री-यूजेबल) रॉकेट रूमी-1 इस शनिवार को लॉन्च होगा। गगन यान का परीक्षण भी इस माह के अंत में किया जाएगा। हाल ही में चंद्रयान-3 सैटेलाइट से पता चला है कि चांद की सतह के भीतर भी हेवी मेटल्स हैं। ये जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक डॉ. पुनीत स्वरूप ने यहां के विद्यार्थियों से साझा की। वे कालिदास संस्कृत अकादमी में शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय द्वारा रखे कार्यक्रम में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। उन्होंने चंद्रयान-3 और आगामी गगन यान मिशन की जानकारी भी दी। कहा कि अंतरिक्ष यात्री मानव-रोबोट 'व्योममित्र' को गगन यान अंतरिक्ष में ले जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत अब दूसरे देशों को सहयोग करने की स्थिति में आ गया है।

केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई टली

नई दिल्ली(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। इसके साथ ही केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह गुरुवार रात आठ बजे उन्हें दिया गया।

केजरीवाल पर सीबीआई जांच की अनुमति

नई दिल्ली (ईएमएस)। सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली की एक कोर्ट को जानकारी दी कि उसे दिल्ली शराब नीति मामले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने यह जानकारी विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दी गई, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की है। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को समाप्त होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।

बता दें कि इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला। उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। सीबीआई ने अदालत से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का और समय मांगा है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।

सेना का मानवरहित यान पाकिस्तानी सीमा में पहुंचा, भारत ने वापस मांगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। तकनीकी खराबी के चलते भारतीय सेना का एक मानवरहित यान यानी यूएवी नियंत्रण से बाहर होकर पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गया। जब भारतीय सेना को पता चला कि यह यूएवी पाकिस्तानी सैनिकों के पास है तो सेना ने पाकिस्तानी सेना को हॉटलाइन से संदेश भेजकर उसे वापस लौटाने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक, यह यूएवी भारतीय सीमा में प्रशिक्षण उड़ान पर था। मगर, सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर तकनीकी खराबी के कारण यह नियंत्रण से बाहर हो गया। यह भारत के भीम्बर गली सेक्टर के सामने पाकिस्तान के निकियाल सेक्टर में चला गया।

रिपोर्टों के जरिए जब सेना को पता चलाकियूएवीपाकिस्तानी सीमा में पाकिस्तानी सैनिकों के पास है तो उसने हॉटलाइन से संदेश भेजा। इसमें कहा गया कि यूएवी को लौटा दिया जाए। पाकिस्तान की ओर से इसे इसका क्या जवाब आया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक में हुआ जमकर हंगामा

नई दिल्ली (ईएमएस)। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के कई प्रावधानों पर सख्त ऐतराज जताते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों से जवाब तलब किए। बैठक के दौरान सदस्यों के बीच कई बार नोक-झोंक भी हुई। जेपीसी की अगली बैठक 30 अगस्त को होगी।

जेपीसी की कई घंटे तक चली बैठक में सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों पर अपने विचार दर्ज कराने के साथ कई सुझाव भी दिए। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, आप के संजय सिंह, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और डीएमके के ए राजा सहित कई विपक्षी सदस्यों ने कलेक्टर को अधिक अधिकार देने पर सवाल उठाए।

विपक्षी सदस्यों ने वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के कदम सहित कई खंडों की आवश्यकता पर प्रश्न उठाए। हालांकि, कई सदस्यों की शिकायत थी कि अधिकारी उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। इसको लेकर कुछ सदस्यों ने नाराजगी भी जताई। एक सदस्य ने कहा कि जेपीसी की अगली बैठक 30 अगस्त को होगी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक में सभी सदस्यों को आश्वासन दिया कि समिति विभिन्न मुस्लिम निकायों सहित सभी हितधारकों से बात करेगी। जेपीसी की बैठक शुरु होने से पहले मीडिया से बात करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति विधेयक पर विस्तार से चर्चा करेगी और इस पर चिंताओं पर भी चर्चा करेगी।

जगदंबिका पाल ने कहा कि विभिन्न हितधारकों की आवाज सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि जेपीसी सभी 44 संशोधनों पर चर्चा करेंगे और अगले सत्र तक एक अच्छा और व्यापक विधेयक लाएंगे। समिति विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न मुस्लिम निकायों को बुलाकर उनके विचार सुनेगी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 वापस लाने का समर्थन करती है : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे 10 सवाल

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के बीच गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर सत्ता की भूख मिटाने के लिए बार-बार देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे हैं।

अब अमित शाह ने इस चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सत्ता के लालच में देश की एकता और सुरक्षा को बार-बार जोखिम में डालने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके एक बार फिर अपनी नापाक मंशा को उजागर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में किए गए वादों को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल इस प्रकार हैं :-

1) क्या कांग्रेस 'नेशनल कांफ्रेंस' के जम्मू-कश्मीर में फिर से 'अलग झंडे' के वादे का समर्थन करती है?

2) क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35ए को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करती है?

3) क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बजाय पाकिस्तान से बातचीत करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?

4) क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा व्यापार शुरू करने के फैसले का समर्थन करते हैं, जिससे सीमा पार आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा?

5) क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को लाने का समर्थन करती है?

6) इस गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी के आरक्षण विरोधी रुख को उजागर कर दिया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कांफ्रेंस के वादे के साथ है?

7) क्या कांग्रेस चाहती है कि 'शंकराचार्य पर्वत' को 'तख्त-ए-सुलिमान' और 'हरि पर्वत' को 'कोह-ए-मारन' के नाम से जाना जाए?

8) क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार में धकेलने और उसे चुनिंदा पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सौंपने की राजनीति का समर्थन करती है?

9) क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है?

10) क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को स्वायत्तता (ऑटोनॉमी) देने की नेशनल कांफ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं?

बदलापुर की घटना पर महाराष्ट्र बंद का फैसला एमवीए ने लिया वापस

मुंबई (ईएमएस)। बदलापुर की घटना पर महाराष्ट्र बंद का फैसला महाविकास आघाडी (एमवीए) ने वापस ले लिया है। एमवीए ने 24 अगस्त को दोपहर दो बजे तक बंद बुलाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद बुलाने को असंवैधानिक करार दिया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश और फिर शरद पवार की अपील के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हड़ताल एक लोकतांत्रिक अधिकार है। कोर्ट का फैसला स्वीकार्य नहीं है लेकिन हम कोर्ट का सम्मान करते हुए इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लेकिन हम नहीं रुकेंगे। आंदोलन से ही आजादी मिली है। ठाकरे ने कहा कि क्या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं करना है? इसका कोई मतलब नहीं है। ठाकरे ने कहा कि उनके कुछ पसंदीदा लोग हैं। वे हमेशा अदालत जाते हैं। फैसला लेकर आते हैं। वे पिछले दिनों मराठा आरक्षण के ख़िलाफ़ भी गए थे।

हमने कल बंद की घोषणा की थी। पवार साहब और पटोले बाहर हैं, इसलिए हम साथ बैठकर कोई फैसला नहीं ले सके। हमने फोन पर बात की। पवार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। हम कल बैठेंगे और चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि यह भविष्य में बंद नहीं होगा। हड़ताल एक लोकतांत्रिक अधिकार है।

ज्ञात रहे कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को कानूनी निर्देश दिया था कि किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से अनुमति नहीं है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं। हम राज्य को बी जी देशमुख फैसले के अनुसार सभी कदम उठाने का निर्देश भी देंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने भी एक्स पर पोस्ट करके महाविकास अघाडी के नेताओं से कल का बंद वापस लेने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट बोला-देशभर में लागू होगी बीएनएस की धारा 479

हिरासत में एक-तिहाई वक्त काट चुके विचाराधीन कैदियों को मिलेगी जमानत

नई दिल्ली(ईएमएस)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएस) की धारा 479 को 1 जुलाई से पहले दर्ज किए गए सभी विचाराधीन मामलों में लागू किया जाएगा। जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने देशभर के जेल अधीक्षकों से कहा- वे धारा 479 में दी गई हिरासत की अवधि का एक तिहाई समय पूरा कर चुके कैदियों के आवेदनों पर कार्रवाई करें। इसे 3 महीने के अंदर निपटाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने देश की जेलों में भीड़ भाड़ से निपटने के लिए अक्टूबर 2021 में नजर बनाए हुए है। इस मामले पर खुद ही एक्शन लेते हुए इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। बता दें, यह धारा विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि से संबंधित है।

जेलों में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी

पिछली सुनवाई में सीनियर एडवोकेट और एमिकस क्यूरी (कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए वकील) गौरव अग्रवाल ने धारा 479 के तहत विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि से जुड़े प्रावधान पर कोर्ट का ध्यान खींचा था। उन्होंने कहा था कि धारा 479 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी विशेष कानून के तहत किसी अपराध के लिए तय सजा का एक तिहाई वक्त हिरासत में रह चुका है, तो उसे कोर्ट जमानत पर रिहा करे। उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। गौरव अग्रवाल ने कहा था कि इससे जेलों में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट का ई-प्रिजन मॉडयूल की जरूरत पर जोर

मामले में न्यायमित्र (एमिकस क्यूरे) के तौर पर काम कर रहे सीनियर वकील विजय हंसारिया ने कैदियों में लॉ अवेयरनेस की कमी का हवाला देते हुए कहा कि दोषियों को बताया नहीं जाता कि वे कानूनी सेवा प्राधिकरण के जरिए अपीलीय अदालतों में जाकर अपने मामले से जुड़ी कमियों को दूर करवा सकते हैं और सजा से बच सकते है। हंसरिया के तर्क पर कोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म ई-प्रिजन मॉडयूल की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ई प्रिजन मॉडयूल इस तरह की समस्याओं को आसानी से निपटाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने ओपन जेल का सुझाव दिया था

इसी मामले को लेकर 9 मई को कोर्ट ने कहा था कि ओपन या सेमी ओपन जेल कैदियों को दिनभर जेल परिसर से बाहर काम करने और शाम वापस जेल में लौटने का ऑप्शन देती है। ओपन जेल कैदियों को समाज में घुलने-मिलने और उनके साइकोलॉजिकल प्रेशर को कम करने में भी मदद करेगी। साथ ही कैदियों की आजीविका में भी सुधार करेगा।

जेलों में आधे कैदी गैर संगीन अपराध के

गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि देश की जेलों में साढ़े पांच लाख कैदी हैं। कैदियों की कुल संख्या में करीब आधे गैर संगीन अपराधों के कैदी हैं। गैर संगीन अपराध के अंडर ट्रायल वालों की संख्या 2 लाख है। इनमें ज्यादातर तो अधिकतम सजा से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।

जन हितैषी

जन हितैषी

कानून बनाने मात्र से नहीं रुकेंगे अपराध

कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की एक रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद अमानुषिक तरीके से हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला संज्ञान में लिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में देवी स्वरूपा तीन से चार वर्ष की कन्याओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई। कई दिनों तक जब कार्रवाई नहीं हुई तो लोग सड़कों पर उतरे। रेलवे ट्रैक बंद कर दिया। तब जाकर मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। दोनों ही घटनाओं में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने चिंता जताकर कोर्ट के अंदर बयान देकर, एक तरह से पल्ला झाड़ने का काम किया है। मणिपुर की घटनाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। कमेटी भी गठित कर दी थी। लेकिन अभी भी मणिपुर में क्या हो रहा है। इसे आसानी से देखा और समझा जा सकता है। इतने कड़े कानून होने के बाद भी देश के सभी राज्यों में 90 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं रोजाना हो रही हैं। बिहार के मुजफ्फरनगर में एक दलित युवती के गुप्तांग में 50 से ज्यादा चाकू से वार किए गए। वह गरीब दलित युवति थी उसके समर्थन में लोग सड़कों पर नहीं उतरे। जिसके कारण यह घटना फाइलों में दबकर रह गई। अपराधिक घटनाओं को रोकने एवं अपराध होने के बाद पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब भी कोई अपराधिक घटना होती है। शासन और प्रशासन द्वारा पुलिस के जांच अधिकारी पर जिस तरह का दबाव बनाया जाता है। वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। विशेष रूप से न्यायपालिका से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। जब अपराध होता है, उस समय थाना इंचार्ज को तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने का अधिकार और दा?यित्व है। पिछले कई दशकों में यह सिस्टम अघोषित रूप से बदल गया है। जब भी कोई अपराध थाना क्षेत्र में होता है। इसकी सूचना थाना प्रभारी द्वारा अपराध दर्ज करने के पहले वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है। कोई संवेदनशील घटना होती है, तो उस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। उसके बाद थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। रिपोर्ट दर्ज करना है या नहीं, पहले जांच करो,फिर रिपोर्ट दर्ज करना, कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज करना है। अपराधी को बचाना है,या आरोपी को शिकंजे में कसना है। इसका निर्देश थाना प्रभारी को वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मिलता है। इस कारण ?रिपोर्ट दर्ज करने में कई घंटों की देर होती है। कार्यवाही में भी ?विलम्ब होता है। इस बीच अपराध से संबं?धित सबूतों से छेड़छाड़ होती है। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग राजनेताओं की अनुशंसा पर होते हैं। राजनीति में जिस तरह से अपराधिक प्रवृत्ति वाले राजनेताओं का हस्तक्षेप बढ़ा है। उसके बाद किसी भी अपराध की सही जांच और सही कार्रवाई नहीं हो रही है। रिपोर्ट दर्ज करने, जांच करने और मुकदमा पेश करने का अधिकार और जिम्मेदारी कानून की किताबों में थाना प्रभारी की है। वास्तविक स्थिति ठीक इसके विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अपराधिक मामले पेश होते हैं। जो मामले पेश होते हैं उसमें सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन जांच अ?धिका?रियों द्वारा नहीं किया जाता है। झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। उसके बाद भी न्यायपालिका की चुप्पी से अपराधिक घटनाएं रुकने के स्थान पर बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद कई कड़े कानून बनाए गए। जल्द न्याय देने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई। यह सब कागजों में है। इनका पालन पुलिस, जांच अधिकारी,शासन-प्रशासन एवं न्यायालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है। न्यायालय में केस डायरी और चार्ज सीट में जानकारी उपलब्ध होती है। उसके बाद भी न्यायालय सही जांच और सही कार्यवाही नहीं करने पर चुप रहती है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट ने यौन उत्पीड़न के मामले की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ। रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस को नियमानुसार आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। महिला खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर में कई दिनों तक प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। यह सारे देश ने देखा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस तमाशे को देखते रहे। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इस तरह के मामलों में टिप्पणी करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह से आम नागरिकों को न्याय मिलेगा। न्यायपालिका की स्थिति हाथी के दांत की तरह हो गई है। दांत तो है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। न्यायपालिका की भूमिका को लेकर जिस तरह के सवाल आज देश में उठ रहे हैं। यह चिंता का विषय है। ऐसा लगता है न्यायपालिका के ऊपर सरकार का दबाव है। जिसके कारण न्यायालय सरकार और सरकारी मशीनरी के खिलाफ कोई निर्णय नहीं कर पाती है। कानून कोई भी बना दिए जाएं, यदि उनका पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। उसके परिणाम कभी नहीं ?मिलेंगे। विशेष रूप से यौन अपराधों को लेकर सरकार ने कड़े से कड़े कानून बनाए हैं। इसके बाद भी अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। सभी अपराधिक मामले अदालत तक जाते हैं। अदालतें अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाती है। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायपालिका को विशेष अधिकार हैं। हर स्तर पर न्यायपालिका,जांच एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों और लापरवाही पर समय-समय पर आदेश जारी कर सकती हैं। जांच अधिकारियों को दंडित करने और जांच सही हो इसे निर्देशित करने का भी उन्हें अधिकार है। जब अदालतों से इस तरह के कोई आदेश नहीं होते हैं। तब जांच अधिकारी के पास केवल एक ही विकल्प होता है। जैसा उसके उच्च अधिकारी कह रहे हैं। उसके अनुसार वह काम करे। वर्तमान स्थिति में अपराधिक घटनाओं को रोक पाना पुलिस के बस की बात नहीं है। भीड़तंत्र और राजतंत्र जो चाहता है। वही हो रहा है। कानून की किताबें आम लोगों के उत्पीड़न के लिए हैं। कानून के नाम पर आम आदमी का उत्पीड़न हो रहा है। समर्थ लोगों के लिए यही कानून, बट- किंतु-परंतु के सिद्धांत पर काम करते हुए बृजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधियों का बचाव करते हैं यही सच है। बृजभूषण शरण सिंह समर्थ था। कानून ने उसका बचाव किया। जिनका उत्पीड़न हुआ,उन्हें न्याय नहीं मिला। इस तरह का संदेश जब देश में जाता है। तब अपराधों पर नियंत्रण होगा,इसकी कल्पना करना भी व्यर्थ है। जब अति होने लगती है। तो समय खुद न्याय करने लगता है। यह न्याय भगवान का होता है। इसके लिए न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना पड़ता है। बंग्लादेश में यही हुआ है।

असम के नागांव 14 साल की लड़की से गैंगरेप

नागांव (ईएमएस)। असम के नागांव जिले में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। घटना तब हुई, जब नाबालिग टयूशन से घर लौट रही थी। इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्टूडेंट यूनियन ने बंद का आह्वान किया है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना नागांव जिले में उस समय हुई, जब लड़की टयूशन से लौट रही थी। यहां 14 साल की लड़की टयूशन से निकली थी, तभी रास्ते में तीन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बच्ची बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिली। लोगों ने जब लड़की को बेहोशी की हालत में देखा, फौरान पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गैंगरेप की बात सामने आई है। वहीं स्टूडेंट यूनियन ने इलाके में बंद का आह्वान किया।

इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने कहा कि जिन अपराधियों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने का साहस किया, उन्हें कानून छोड़ेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए मानवता के खिलाफ अपराध बताया। उन्होंने घटना पर गुस्सा जाहिर कर आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। उन्होंने लिखा कि ढिंग में नाबालिग के साथ हुई घटना मानवता के खिलाफ अपराध है। घटना ने हमारी सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा।

शब्द पहेली - 8107

■	1		2	■	3		4	■
5		■		■		■	6	7
	■	■	8	9		10	■	
11		12	■		■	13		
■	■	14		■	15		■	■
16			■	17	■	18		19
	■	■	20		21	■	■	
22	23	■		■		■	24	
■	25			■	26			■

बाएँ से दाएँ

1. पाबंदी, संयम, पाश-3
3. मनुष्य, इंसान-3
5. शारीरिक ऊंचाई-2
6. नलका, टूंटी
8. प्रलय, महासंकट-4
11. दही से बना खाद्य पदार्थ-3
13. निर्माण, निर्मिती-3
14. हुनर, आर्ट-2
15. उम्मीद, आशा-2
16. खाना बनाना-3
18. असफल, अनुतीर्ण-3
20. आभास, भास-3
22. वध-2
24. जी, इच्छा, चित-2
25. सब्जी का सड़ना, बर्फ का पिघलना-3
26. याद करना-3

ऊपर से नीचे

1. हड़ताल, स्थिर, रुका हुआ-2
2. लवण -3
3. विश्राम, राहत-3
4. मछली, मत्स्य, राशि चक्र की एक राशि-2
5. बूंद-3
7. शरमाना-3
9. दोस्त, मित्र-2
10. बहुत प्यासा होना-4
12. एकटक निहारना-3
16. शरण, आश्रय-3
17. सम्मान-2
19. चिंतन-3
20. मकान, इमारत-3
21. कमी, थोड़ा-3
23. तज देना-2
24. इंकार, मनाही-2

शब्द पहेली -8106 का हल

न	भ	■	न	र	म	■	मा	त
म	■	शा	म	■	द	म	■	प
क	न	क	■	ज	■	ना	प	ना
■	मा	■	ख	न	क	■	र	■
रा	ज	दा	र	■	स	रो	व	र
■	गा	■	ल	गा	म	■	रि	■
र	ह	न	■	ल	■	मि	श	न
म	■	ख	त	■	पा	त्र	■	जा
ल	य	■	वा	च	क	■	ता	त

Jagrutidaur.com, Bangalore

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक है। पिछले कुछ समय से स्कूली बच्चों में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से डरावनी एवं खौफनाक है। चिंता का बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता घर करने लगी है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और खेलकूद में व्यस्त रहना चाहिए, उसमें उनमें बढ़ती आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता एक अस्वाभाविक और परेशान करने वाली बात है। कई घटनाओं में स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू या किसी घातक हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अमेरिका की तर्ज पर भारत के बच्चों में हिंसक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती है। यह दुष्प्रवृत्ति बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर तो नकारात्मक प्रभाव डाल ही रही है, इसे भविष्य में समाज की शांति के लिए बड़ा खतरा भी मानना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर के स्कूल में दो छात्रों के आपसी विवाद में चाकू मारने से एक छात्र की मौत भी बच्चों में पनप रहे इसी हिंसक बर्ताव का घिनौना एवं घातक रूप है।

बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता एवं हिंसा पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है! पाठयक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके, बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों का दायरा, संगति, सोशल मीडिया या टीवी से लेकर उसकी सोच-समझ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से तैयार होने वाली उनकी मन:स्थितियों के बारे में सरकार, समाजकर्मी एवं अभिभावक क्या समाधान खोज रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बच्चों के बस्ते की औचक जांच की व्यवस्था की अपनी अहमियत हो सकती है। मगर जरूरत इस बात की है कि बच्चों के भीतर बढ़ती हिंसा और आक्रामकता के कारणों को दूर करने को लेकर गंभीर काम किया जाए। उदयपुर की घटना के पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाना भी ज्यादा जरूरी है। तहकीकात स्कूल की व्यवस्थाओं की भी होनी चाहिए कि आखिर बच्चा स्कूल में हथियार लेकर कैसे आ गया? इसमें दो राय नहीं कि किशोरवय में राह भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। उम्र के इस पड़ाव पर उनको सही राह दिखाने की जिमेदारी परिजन और शिक्षक की ही होती है। आज दोनों ही कहीं न कहीं अपनी जिमेदारी से दूर होते नजर आ रहे हैं। स्कूल में केवल किताबी ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं अर्थप्रधान दुनिया में माता-पिता के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा।

'मन जो चाहे वही करो' की मानसिकता वहां पनपती है जहां इंसानी रिश्तों के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, जहां व्यक्तिवादी व्यवस्था में बच्चे बड़े होते-होते स्वछन्द हो जाते हैं। 'मूड ठीक नहीं' की स्थिति में घटना सिर्फ घटना होती है, वह न सुख देती है और न दु:ख। ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी अनंत शक्तियों को बौना बना देता है। यह दकियानूसी ढंग है भीतर की अस्तव्यस्तता को प्रकट करने का। पारिवारिक एवं सामाजिक उदासीनता एवं संवादहीनता से ऐसे बच्चों के पास सही जीने का शिष्ट एवं अहिंसक सलीका नहीं होता। वक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे बच्चों में मान-मर्यादा, शिष्टाचार, संबंधों की आत्मीयता, शांतिपूर्ण सहजीवन आदि का कोई खास ख्याल नहीं रहता। भौतिक सुख-सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। भारतीय बच्चों में इस तरह का एकाकीपन उनमें गहरी हताशा, तीव्र आक्रोश और विषैले प्रतिशोध का भाव भर रहा है। वे मानसिक तौर पर बीमार बन रहे हैं और अपने पास उपलब्ध खतरनाक एवं घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हत्याकांड कर बैठते हैं। शिक्षकों और परिजनों से संवादहीनता के चलते बच्चों ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को संवाद का जरिया बना लिया है। कई बार टी.वी. पर हिंसक कार्यक्रम देखने आदि से बच्चों में हिंसक व्यवहार बढ़ जाता है। घर में लगातार बंदूकें, चाकू आदि देखते रहने से भी बच्चों का व्यवहार हिंसक हो जाता है। वैसे भी अगर बच्चों को किसी भी बात के लिए मना नहीं करेंगे, टोकेंगे नहीं तो उन्हें अच्छे-बुरे की पहचान कैसे होगी। एक ऑनलाइन सर्वे में माता-पिता ने कहा था कि बच्चों को गलत काम की सजा भी मिलनी चाहिए, वरना उनके मन में किसी भी बात के लिए डर नहीं रहेगा और हो सकता है वे ऐसे अपराधों को भी अंजाम देने लगें, जिनके परिणामों के बारे में उन्हें पता नहीं।

स्कूली बच्चों में पिछले कुछ समय से हिंसक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जो समाज के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। मनोविज्ञानी यह मानते हैं कि मोबाइल पर पबजी जैसे खतरनाक गेम और वेब सीरिज बच्चों को हिंसक बना रही है। लेकिन, इसके पीछे न सिर्फ स्कूल का वातावरण, बल्कि लाड-प्यार में अंधे अभिभावकों का रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं है। बच्चों में हिंसक व्यवहार के संकेत, जैसे गलत भाषा का प्रयोग करना, समझाने पर भी गुस्सा करना, कोई भी बात समझाने पर चीजें फैंकने लगना, मां-बाप को ही मारने दौडना, लोगों के बारे में गलत बोलना, गलत आदतों में पडना, भाई-बहन के लिए स्नेह न रखना, लड़ाकू प्रवृत्ति का होना, हमेशा उदास रहना, संवेदनहीन और चिड़चिड़े रहना, बार-बार जोश में आना आपको नजर आ सकते हैं। एकल परिवारों में माता-पिता इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास बच्चों से बात करने का ज्यादा समय नहीं होता। वे अक्सर इस बात पर भी नजर नहीं रख पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उनके दोस्त कौन-कौन से हैं। दोस्त उन्हें चिढ़ाते भी हैं कि अरे! तुम्हारे माता-पिता कैसे हैं, जो तुम्हें ऑनलाइन खेल भी नहीं खेलने देते। इससे बच्चों में हीनता और अपने घर वालों के प्रति नफरत का भाव पैदा होता है, जो अपराध के रूप में बाहर निकलता है। फिजिकल, ओरल या सैक्सुअल रूप में गलत व्यवहार, घरेलू वातावरण न मिलना, माता-पिता द्वारा बच्चों की अनदेखी, दर्दनाक घटना होने या फिर स्ट्रैस होना, बच्चों को धमकाना, फैमिली प्रॉब्लम, नशीली चीजों का सेवन, शराब और अन्य गलत चीजों के सेवन से बच्चों में आक्रामकता बढ़ सकती है और वे हिंसक हो सकते हैं।

ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट विश्वविद्यालय की ओर से किशोरों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में 35.8 प्रतिशत से ज्यादा किशोर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अकारण भय, पारिवारिक अथवा सामाजिक हिंसा, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं। घर में बच्चों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित, और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने के साथ अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। स्कूलों में काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की व्यवस्था होनी चाहिए, जो बच्चों की मानसिक समस्याओं को समझें और उनका समाधान कर सकें। सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षकों को बच्चों के आचरण और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। ऐसा करने पर वे बच्चों के चाल-चलन की बारीकी से निगरानी कर सकेंगे। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा?

बच्चों से जुड़ी हिंसा की इन वीभत्स एवं त्रासद घटनाओं से जिन्दगी इतनी सहम गयी है कि गलत धारणाओं को मिटाने के लिये इस तरह की विकृत सोच एवं तथाकथित विकास से जुड़े शत्रु को पीठ के पीछे नहीं, सामने रखना होगा। सोचना होगा कि खुशहाली का पैमाना सिर्फ आर्थिक सम्पन्नता, शक्ति एवं सत्ता नहीं हो सकता। हमें मानवीय मूल्यों के लिहाज से भी विकास की परख करनी होगी। बच्चों के भीतर हिंसा मनोरंजन की जगह ले रही है। इसी का नतीजा है कि छोटे-छोटे स्कूली बच्चे भी अपने किसी सहपाठी से रंजिश के चलते उस पर गोली चलाते देखे गये हैं। (लेखक – ललित गर्ग/ईएमएस) (लेखक,पत्रकार, स्तंभकार)

महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, सरकार और समाज

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर की बलात्कार की घटना के बाद हत्या के बाद से देशभर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मुश्किल में मरीज हैं और बिना इलाज के अस्पतालों से लौट रहे हैं। डॉक्टर कार्य स्थल पर अपनी सुरक्षा को लेकर केंद्रीय संरक्षण अधिनियम की मांग कर रहे हैं। इस बिल को 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल का मकसद डॉक्टर्स के साथ हिंसा को परिभाषित करना और ऐसा करने वाले शख्स के लिए दंड देने का प्रावधान करना है। इधर

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी को भयावह घटना करार देते हुए देश भर में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के संबंध में संस्थागत विफलता पर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा दूसरों की स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीनी बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता।

कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तंत्र स्थापित करने के लिए 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित की है। कोर्ट ने डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए समाज और मरीजों के हित में काम पर लौटने की अपील भी की। इसके साथ ही कोर्ट ने डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी पर सवाल उठाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई हैं, जो बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी को मानते हुए कहा कि दुष्कर्म पीड़ित के नाम को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा एक बड़ी समस्या है। 1.4 अरब की आबादी वाले देश में 2022 में औसतन प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गईं। भारत में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किये गये। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले 2021 में 4,28,278 जबकि 2020 में 3,71,503 प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सिलसिले में हर घंटे लगभग 51 प्राथमिकी दर्ज की गईं।

आंकड़ों के अनुसार प्रति एक लाख आबादी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 66.4 प्रतिशत रही जबकि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दायर करने की दर 75.8 रही। एनसीआरबी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ अधिकांश (31.4 प्रतिशत) अपराध पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता किए जाने के थे, इसके बाद महिलाओं के अपहरण (19.2 प्रतिशत), शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला (18.7 प्रतिशत) और बलात्कार (7.1 प्रतिशत) के मामले रहे। आंकड़ों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सबसे अधिक 65,743 प्राथमिकी दर्ज की गईं, इसके बाद महाराष्ट्र (45,331), राजस्थान (45,058), पश्चिम बंगाल (34,738) और मध्य प्रदेश (32,765) रहे। एनसीआरबी के अनुसार पिछले साल देश में जितने मामले सामने आए उनमें से 2,23,635 (50 प्रतिशत) इन पांच राज्यों में दर्ज किए गए।

गृह मंत्रालय ने देश में महिलाओं की सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली करने के लिए 28 मई, 2018 को एक नया ''महिला सुरक्षा प्रभाग'' स्थापित किया है। और समग्र रूप से न्याय के तीव्र और प्रभावी प्रशासन के माध्यम से और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करके उनमें सुरक्षा की अधिक भावना उत्पन्न करना। नया प्रभाग इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए नीति निर्माण योजना समन्वय निर्माण और परियोजनाओं / योजनाओं को लागू करने के साथ.साथ जेल सुधार मानव तस्करी विरोधी और संबंधित विषयों के लिए जिम्मेदार है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी और टैक्नोलॉजी का बढ़ा हुआ उपयोग और फोरेंसिक विज्ञान और अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड के लिए एक सहायक ईको सिस्टम को सक्षम करना शामिल है।

9 अगस्त को घटी इस घटना से 16 दिसंबर 2012 के निर्भया प्रकरण की भयावह याद लोगों को आ रही है।2012 के बाद सीधे 2024 में ऐसी घटना घटित हुई हो, बल्कि इस बीच इस तरह के अपराध की एक लंबी फेरिस्त बन गई, जिसे सियासत ने टूटने ही नहीं दिया। यह सोचकर ही वितृष्णा से भर जाता है। यह सोचने को मजबूर कर देता है कि हम कितने गिरे हुए समाज में तब्दील हो चुके हैं, जिसमें एक स्त्री पर हुए भयानकतम अत्याचार को सत्ता हासिल करने का माध्यम बनाने में कोई संकोच नहीं होता। क्योंकि तब जिन लोगों से उम्मीद थी कि वे राजधर्म और नैतिकता के धर्म का पालन करके एक स्त्री का साथ देंगे, उन लोगों ने आंखें मूंद ली थीं और अब भी वही रवैया नजर आ रहा है। इसी तरह की घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना की है। जहां एक दलित को, एक नाबालिग को शिकार बनाया गया। पारु थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में दलित युवती की हत्या मामले में नए-नए करनामें सामने आ रहे हैं।

फिलहाल सबका ध्यान प.बंगाल पर केन्द्रित है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग से लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग हो चुकी है। ममता बनर्जी को महिला होने का वास्ता भी दिया जा रहा है। उनके साथ टीएमसी की मुखर सांसद महुआ मोईत्रा पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा बड़े हक से पूछ रहे हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी कोलकाता कब जाएंगे।

कायदे से इस समय दो ही लोगों से जवाब मांगे जा सकते हैं, एक हैं ममता बनर्जी और दूसरे हैं नरेन्द्र मोदी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी, मगर इसमें जो लोग महिला वाला कोण सामने कर रहे हैं, वह संकीर्ण मानसिकता को ही दिखाता है।

राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ही हैं और प्रियंका गांधी तो कांग्रेस की एक सामान्य पदाधिकारी से अधिक कुछ नहीं हैं। प.बंगाल में कांग्रेस की सत्ता भी नहीं है, न ही केंद्र में कांग्रेस का शासन है, इसलिए इस मामले में कांग्रेस से सवाल किया जाना, राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है।

एक महिला के साथ होने वाले अपराध के दर्द को एक महिला ही क्यों समझे, एक पुरुष क्यों न समझे, यह सवाल समाज को करना चाहिए। इस मामले में महुआ मोईत्रा पर उंगलियां उठाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे एक सांसद ही हैं, न कि प.बंगाल सरकार का हिस्सा। और अगर उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं, तो फिर यही बर्ताव सारे सांसदों के साथ किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने लालकिले के प्राचीर से अपने भाषण में महिला अपराधों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने की बात जरूर कही, लेकिन उनका रवैया भी अब तक चयनित ही रहा है। अगर पश्चिम बंगाल में पहले संदेशखाली और अब कोलकाता बलात्कार कांड पर वे सख्त फैसलों के पक्ष में खड़े दिखते हैं, तो उन्हें मणिपुर, हाथरस, कठुआ, उन्नाव और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जैसे मामलों पर भी यही रुख अपनाना चाहिए था।

इस पूरे प्रकरण में पीड़िता को इंसाफ दिलाने का सवाल सबसे अहम होना चाहिए था, मगर वही अब प्राथमिकता सूची में सबसे आखिरी में दिख रहा है। सियासत के कारण इसमें भ्रामक तथ्यों को फैलाने का जोर बढ़ गया है। मामला फिलहाल सीबीआई के सुपुर्द है, तो उसे उसका काम करने देना चाहिए। लेकिन नियमों, कानूनों का उल्लंघन करते हुए कहीं पीड़िता की पहचान उजागर की जा रही है, कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ब्यौरा दिया जा रहा है और उसमें भी सच-झूठ का घालमेल है। इस मामले में प.बंगाल पुलिस ने अब भाजपा के दो और टीएमसी के एक नेता को नोटिस भी भेजा है। लेकिन इस नोटिस के बावजूद गलत सूचनाएं या अफवाहें फैला दी गई हैं और अब सोशल मीडिया के जरिए उन्हें देश भर में प्रसारित किया जा चुका है। इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है।

निर्भया मामले के बाद यौन हिंसा के विरुद्ध कानूनों को कठोर बनाया गया था।बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए भी कड़े प्रावधान हैं। पर कानून अपराधों को बढ़ने से रोक नहीं पाये हैं। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का बढ़ना केवल अधिक सुरक्षा मुहैया कराने और न्याय पाने का ही मामला नहीं है यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। महिलाओं की भागीदारी कम होने के साथ मेहनताने में लैंगिक अंतर का मसला भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। यदि इन दोनों मुद्दों पर समुचित ध्यान दिया जाए, तो रोजगार, कमाई और उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी होगी।भारत अपनी आधी मानव पूंजी की प्रभावी वृद्धि क्षमता की अनदेखी कर रहा है।

महिला सुरक्षा को लेकर समाज सतर्क रहे और सरकार से जवाबदेही चाहे, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यह सतर्कता और उद्वेलन सत्ता हासिल करने के षडयंत्र की तरह इस्तेमाल हों, तो फिर समाज को सोचना चाहिए कि आखिर वह क्यों अपनी भावनाओं का इस तरह दोहन होने दे रहा है। अभी निर्भया प्रकरण को लेकर फिर से कांग्रेस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निर्भया के इलाज से लेकर दोषियों को पकड़ने तक सबमें तत्परता दिखाई। हालांकि तब बीजेपी लोगों के आक्रोश को मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित की सरकारों के खिलाफ इस्तेमाल करने में सफल हो गई थी। अब एक बार फिर वही खेल खेला जा रहा है। जबकि अब सरकार से लोगों को पूछना चाहिए कि इस देश में महिलाएं घरों से लेकर कार्यस्थलों तक हर जगह कब सुरक्षित महसूस करेंगी। (लेखक – कुमार कृष्णन/ईएमएस)

खेल - समाचार

ब्रांड वैल्यू में सबसे आगे निकले नीरज, मनु और विनेश भी आगे बढ़े

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में अब क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के स्टार खिलाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ओलंपिक रजत पदक विजेता भालाफेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ब्रांड वैल्यू के मामले में सबसे आगे निकल गये हैं। नीरज ने ब्रांड वैल्यू के मामले में ऑलराउंडर हार्दिक पांडया को भी पछाड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीरज भारत के सबसे अमीर एथलीट बन गए हैं। इसके साथ ही वह सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाले भारत के पांचवे खिलाड़ी बन गए हैं।

पेरिस ओलंपिक खेलों में नीरज ने दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक जीता था जबकि पिछले ओलंपिक में वह स्वर्ण विजेता रहे थे। इस प्रकार वह लगातार दो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। रिपोर्ट के तहत पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीत पाने के बाद भी उनकी ब्रांड वैल्यू में करीब 100 करोड़ रुपए की तेजी आई है। पेरिस ओलंपिक से पहले नीरज की ब्रांड वैल्यू 248 करोड़ रुपए थी जो अब 335 करोड़ रुपए हो गई है।

नीरज वर्तमान में 21 ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं पांडया के पास 20 ब्रांड हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू 318 करोड़ रुपए है। नीरज ने पेरिस ओलंपिक के बाद अपनी फीस भी बढ़ा दी है। पहले वह एक ब्रांड से एक साल के लिए करीब 03 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। लेकिन अब उनकी फीस चार से 4.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

वहीं पेरिस ओलंपिक की निशानेबाजी में दो कांस्य पदक जीतकर रिकार्ड बनाने वाली महिला निशानेबाज मनु भाकर और पहलवान विनेश फोगाट की भी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। मनु के पास पास विज्ञापनों की भरमार हैं। उन्होंने अपनी फीस भी बढ़ा दी है। पेरिस ओलंपिक से पहले वह एक ब्रांड से सालाना 25 लाख रुपए लेती थी, लेकिन अब उनकी फीस 1.50 करोड़ रुपए हो गई है।

अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप : भारतीय महिला पहलवान अदिति और नेहा ने खिताब जीते

अम्मान (ईएमएस)। भारतीय महिला पहलवान अदिति कुमारी और नेहा पुलकित ने कैडेट्स टूर्नामेंट के अपने-अपने वर्ग में अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप जीती है। अदिति ने 43 किग्रा भार वर्म में यूनान की मारिया लौइजा गिकिका को फाइनल में 7-0 से हराया। वहीं नेहा ने 57 किग्रा के फाइनल में जापान की सो सुतसुई को 10-0 के अंतर से हराया। महिला पहलवान विनेश फोगाफ के गांव की नेहा ने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और यह खिताब विनेश दीदी और सभी महिला पहलवानों के लिए है। विनेश दीदी हम सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं और यह विश्व खिताब बलाली गांव के साथ-साथ भारत की महिला पहलवानों को भी प्रेरित करेगा।

नेहा के पिता अमित कुमार सांगवान अपनी बेटी की इस सफलता से उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इससे पूरे गांव का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि नेहा ने पिछले सप्ताह ही विनेश के स्वागत के लिए पूरी दोपहर माला बनायी थी। जब वह मंच पर गई थी, तो विनेश ने उससे कहा था कि उसकी तरह लड़कियों को उसका सपना पूरा करना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा, नेहा को अपना पहला विश्व खिताब जीतते देखकर आज विनेश भी बहुत खुश हुई होंगी। यह पूरे बलाली गांव के लिए भी एक खास एहसास है।

राहुल के संन्यास की अफवाह उड़ी

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज केएल राहुल को लेकर सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से फैली थी कि राहुल ने अंतरराट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है पर वह बाद में गलत निकली। दरअसल राहुल ने सोशल मीडिया में एक स्टोरी साझा करते हुए लिखा था कि उन्हें कुछ बताना है। इसके बाद अचानक ही उनकी सोशल मीडिया पर एक स्टोरी साझा होने लगी और उसमें ये दावा किया जाने लगा कि राहुल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इससे सभी प्रशंसक हैरत में पड़ गये पर बाद में जब सच्चाई सामने आई तो सभी ने राहत की सांस ली क्योंकि राहुल ने इस तरह की कोई स्टोरी साझा ही नहीं की। इससे साफ है कि जो उनकी स्टोरी का जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था वह फर्जी निकला। उन्होंने एक स्टोरी जरूर साझा की थी जिसमें लिखा था कि उन्हें किसी चीज की जानकारी देनी है पर संन्यास को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। ऐसे में कुछ लोगों ने गलत जानकारी फैला दी।

पैदल चाल खिलाड़ी भावना जाट पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली (ईएमएस)। नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक (एडीडीपी) पैनल ने भारत की पैदल चाल खिलाड़ी भावना जाट पर 16 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। भावना पर ये पाबंदी इसलिए लगायी गयी है कयोंकि पिछले साल वह अपने ठिकाने की जानकारी देने में असफल रहीं थीं। इसी कारण भावना को पिछले साल अगस्त में ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने बुडापेस्ट में हुई 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 20 किमी पैदल चाल स्पर्धा से निलंबित करते हुए वापस बुला लिया था। वहीं उनका 16 महीने के प्रतिबंध का समय अस्थाई निलंबन की तारीख 10 अगस्त 2023 से शुरू हुआ। इस प्रकार उनका प्रतिबंध इस साल के अंत में 10 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा।

नाडा नियमों के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार उन्हें निलंबित करने का फैसला 10 जुलाई को सुनाया गया था पर इसे अब सार्वजनिक किया गया है। भावना ने मई और जून 2023 में दो डोप जांच भी नहीं करायी थी। इसी कारण उन्हें 2022 के अंत में चेतावनी दी गई थी। भावना ने तब कहा था कि मोबाइल एप में गड़बड़ी के कारण वह नाडा की शर्त पूरी नहीं कर पायी।

पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया : भास्करन

जीता हुआ कांस्य पदक भी स्वर्ण से कम नहीं

चेन्नई (ईएमएस)। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान वासुदेवन भास्करन ने भारतीय टीम की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि उसने पेरिस ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भास्करन ने कहा कहा कि ये कांस्य पदक भी स्वर्ण पदक से कम चमकदार नहीं है। इसका कारण है कि उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया और 10 खिलाड़ियों से खेलते हुए ब्रिटेन के साथ ड्रॉ खेला। भारतीय टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराया। भास्करन ने एक कार्यक्रम में कहा कि यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हम रजत या स्वर्ण पदक हासिल नहीं कर पाये पर ऐसा होता रहता है। मेरा मानना है कि हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ हॉकी खेली। उन्होंने कहा कि मैं इस टीम के प्रदर्शन को स्वर्ण से बेहतर मानता। वहीं अगर स्वर्ण से भी बड़ा प्लैटिनम पदक होता तो टीम को को मिलना चाहिये था। भारतीय टीम ने ओलंपिक की शुरुआत से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार जीत दर्ज की।

1980 मास्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भास्करन ने कहा कि इस टीम के दबाव झेलने की क्षमता भी काफी अच्छी है।ब्रिटेन के खिलाफ टीम ने अधिकतर समय 10 खिलाड़ियों के साथ भी खेला था। भास्करन ने मुख्य कोच क्रेग फुल्टन की रक्षात्मक रणनीति की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि फुल्टन पिछले दो वर्षो से सफलतापूर्वक टीम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी रक्षात्मक प्रणाली अच्छी रही है। यह आक्रामक रणनीति की तरह नजर आती है। भास्करन ने कहा कि कोच से अधिक खिलाड़ियों को श्रेय देना चाहिए। कोच योजना बनाता है पर उन्हें मैदान में अमल में लाने का काम खिलाड़ी करते हैं।

लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे नीरज

लुसाने (ईएमएस)। भारत के शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने यहां अपने अंतिम थ्रो में 89.49 मीटर दूरी तक भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा है। वहीं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर के अंतिम थ्रो के साथ ही पहला स्थान जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने 88.37 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चौथा स्थान यूक्रेन के आर्टुर फेलनर ने हासिल किया, जिनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 83.38 मीटर था। इससे पहले पेरिस ओलंपिक में नीरज ने रजत हासिल करने के दौरान 89.45 मीटर की दूसरी तय की थी। चौथे राउंड के अंत तक चोपड़ा चौथे स्थान पर थे पर पांचवें थ्रो में वह 85.58 मीटर की दूरी तय करने में सफल रहे और शीर्ष तीन में शामिल हो गए।

अर्चना कामथ ने टेबल टेनिस को अलविदा कहा अमेरिका में आगे की पढ़ाई करेंगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। 24 साल की उम्र में ही महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी अर्चना कामथ ने खेल से संन्यास ले लिया है। अर्चना ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। अर्चना ने आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने के कारण ही संन्यास की घोषणा की है। अर्चना कामथ पेरिस ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली भारतीय टीम में शामिल थीं। क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के खिलाफ भारत को जो एक जीत मिली थी, वह अर्चना को ही मिली थी। अब वह पढ़ाई के लिए मिशिगन चली गयी हैं। इस खिलाड़ी ने कहा, 'अगर मैंने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया है तो यह पढ़ाई के प्रति झुकाव के कारण लिया है।

शेयर बाजार हल्की तेजी के साथ बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये बढ़त दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही लिवाली (खरीदारी) हावी रहने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 33.02 अंक बढ़कर 81,086.21 पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 11.65 अंक ऊपर आकर 24,823.15 के पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान वाहन क्षेत्र के शेयर ऊपर आये। वहीं ट्रेड के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 81,231.49 के उच्च और 80,883.26 के निचले स्तर पर पहुंचा जबकि निफ्टी 24,858.40 के उच्च और 24,771.65 के निचले स्तर पर पहुंचा। शुरुआत कारोबार की बात करें तो सेंसेक्स 81,165.65 पर और निफ्टी-50 24,845.40 के लेवल पर खुला।

अमेरिका में सितंबर में फेड की तरफ से दर में कटौती तकरीबन निश्चित है। इसी को देखते हुए आज ग्लोबल मार्केट में निवेशकों ने भी ज्यादा कारोबार नहीं किया।

बाजार में आज ज्यादातर क्षेत्रों में गिरावट रही। निफ्टी में वाहन क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में गिरावट रही। सबसे अधिक लाभ वाले शेयरों में बजाज ऑटो सबसे ऊपर रहा। उसके शेयर 4.74 फीसदी बढ़कर 10,384.45 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए जबकि, इंट्रा डे ट्रेड के दौरान इसके शेयर 10,444.35 के उच्चतम स्तर पर पहुंचे थे। बजाज ऑटो के अलावा, सबसे अधिक लाभ वाले शेयरों में कोल इंडिया, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स और सनफार्मा के शेयर रहे।

बाजार में आज सबसे बड़ी गिरावट रियल्टी के क्षेत्र में रही। इसमें कुल 2.43 फीसदी की गिरावट रही जबकि, टॉप लूजर्स में नंबर-1 पर एलटीआई माइंड्री के शेयर रहे। इसके अलावा, विप्रो, ओएनजीसी, एशियन पेंट्स और टाइटन के शेयरों को भी सबसे अधिक नुकसान हुआ। वहीं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को 1,371.79 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी।

इससे पहले आज सुबह कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की, लेकिन बाद में वैश्विक बाजारों में नरम रुख और आईटी शेयरों में बिकवाली के बीच इनमें गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 37.32 अंक की बढ़त के साथ 81,090.51 अंक पर खुला। एनएसई निफ्टी 18.25 अंक चढ़कर 24,829.75 पर पहुंच गया। बाद में दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त खो दी।

जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.17 फीसदी की गिरावट पर था, जबकि टॉपिक्स सूचकांक 0.04 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ लगभग स्थिर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.13 फीसदी गिरा, जबकि कोस्डेक में 0.79 फीसदी की गिरावट आई। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी, एएसएक्स 200 सूचकांक 0.40 फीसदी की गिरावट पर रहा। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.55फीसदी की गिरावट के साथ 17,543 स्तर पर आ गया।

सरकार बंद कर सकती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना!

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में सोने के बढ़ते आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाई गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना को सरकार बंद कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि यह एक महंगा और जटिल निवेश साधन है। इस कारण सरकार अब आगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं रख सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से इस योजना को बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले ही कयासों का दौर शुरू हो चुका है और बाजार लगभग इस फैसले के लिए तैयार दिख रहा है। सेकेंडरी मार्केट्स में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मांग में तेजी देखने को मिली है। सरकार ने पेपर गोल्ड के तौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 2015 में पेश किया था। आरबीआई इसका प्रबंधन करता है। सरकारी एसजीबी योजना के जरिये बाजार से कम मूल्य पर सोना खरीदने का विकल्प देती है। इसकी मेच्योरिटी अवधि आठ साल है। साथ ही, खरीदारों को 2.5 फीसदी रिटर्न भी मिलता है। इस योजना के पेश होने के बाद से अब तक कुल 67 किस्त जारी हो चुकी है, जिसमें निवेशकों ने 72,274 करोड़ का निवेश किया है। इनमें से चार किस्त पूरी तरह मेच्योर हो चुकी है। 2015 में यह योजना पेश हुई थी, तब इसका इश्यू प्राइस 2,684 रुपये प्रति ग्राम था। 2023 में इसकी मेच्योरिटी पूरी हुई थी, तब रिडम्पशन प्राइज 6,132 रुपये तय किया गया था। इस तरह, निवेशकों को आठ साल में 2.28 गुना मुनाफा हुआ था। दरअसल, 2015 और 2017 के बीच जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के पहले चार किस्तों में निवेशकों की ओर से लगाया गया पैसा दोगुना से भी ज्यादा हो गया है। ऐसे में निवेशकों को रिटर्न सरकार को अपनी जेब से देना पड़ रहा है।

सरकार अगले महीने खुले बाजार में गेहूं बेचना शुरू करेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकार अगले महीने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के भंडार से थोक खरीदारों को खुले बाजार में गेहूं बेचने पर विचार कर रही है। यह फैसला आगामी त्योहारी सीजन में संभावित मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पिछले साल एफसीआई ने जून में खुले बाजार में बिक्री शुरू की थी और 10 मिलियन टन गेहूं की रिकॉर्ड मात्रा थोक खरीदारों को बेची थी। व्यापारियों का कहना है कि मौजूदा आपूर्ति स्थिति पर्याप्त है लेकिन त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने पर कीमतों में वृद्धि की संभावना हो सकती है। वर्तमान में एफसीआई के पास 25.89 मिलियन टन गेहूं का भंडार है, जबकि अक्टूबर 1 के लिए बफर स्टॉक 20.52 मिलियन टन है। एक अधिकारिक नोट के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए 18.4 मिलियन टन गेहूं की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार गेहूं की कीमतों पर निगरानी रखे हुए है, जो पिछले छह महीनों से स्थिर रही हैं। खुले बाजार में गेहूं की बिक्री उस समय शुरू की जाएगी जब कीमतों में वृद्धि की संभावना होगी। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को गेहूं के खुदरा मूल्य की औसत कीमत 28 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो पिछले छह महीनों से स्थिर है। खाद्य मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए एफसीआई के स्टॉक्स से खुले बाजार में 2.5 मिलियन टन गेहूं की बिक्री के लिए आवंटित किया है। एफसीआई गेहूं की बिक्री 2,325 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर शुरू करेगी, जो मौजूदा बाजार की कीमतों से लगभग 2,500 रुपए प्रति क्विंटल कम है।

देश का संगठित स्वर्ण ऋण बाजार अगले पांच साल में हो सकता है दोगुनाः रिपोर्ट

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत का संगठित स्वर्ण ऋण बाजार अगले पांच साल में दोगुना होकर 14.19 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है। देश के स्वर्ण ऋण बाजार पर जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में संगठित स्वर्ण ऋण बाजार की वृद्धि हुई थी और यह 7.1 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन पर पहुंच गया था। इसके मुताबिक पांच साल में 14.85 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर पर सोने के बदले कर्ज का बाजार वित्त वर्ष 2028-29 तक 14.19 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है। रिपोर्ट कहती है कि भारतीय परिवारों के पास भारी मात्रा में सोना है, जिसके 25,000 टन होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय परिवारों के पास मौजूदा सोने की कीमत लगभग 126 लाख करोड़ रुपये है। अगले दो वर्षों में सोने के बदले कर्ज के बाजार में मध्यम वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि सोने के बदले कर्ज देने वाले ऋणदाताओं को कर्ज एवं मूल्य (एलटीवी) रखरखाव और नीलामी से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में नियामक अधिकारियों से बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बाजार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के निष्क्रिय होने से चालू वित्त वर्ष में बाजार की वृद्धि पर असर पड़ेगा। इसके अलावा नकद वितरण पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को रिजर्व बैंक की सलाह, जो नकद वितरण की राशि को 20,000 रुपये तक सीमित करती है, ग्राहकों को असंगठित क्षेत्र पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

गेल, पेट्रोन मिलकर लगाएंगे बायो-एथिलीन प्लांट

नई दिल्ली (ईएमएस)। सार्वजनिक गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कहा कि वह भारत में 500 किलो टन प्रति वर्ष बायो-एथिलीन संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए, अमेरिकी जैव-ईंधन उत्पादक पेट्रोन स्कॉट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गेल ने कहा कि समझौता ज्ञापन (एमओयू) में दोनों कंपनियों के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम में बायो-एथनॉल आधारित संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना का प्रावधान है। गेल देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस परिवहन एवं विपणन कंपनी है, जबकि पेट्रोन एथनॉल, बायो-एथिलीन, जैव-रसायन और विभिन्न जैव-ईंधन परियोजनाओं का उत्पादन करने के लिए बायोमास और अनाज प्रसंस्करण बायोरिफाइनरी परियोजनाएं स्थापित करने में माहिर है। बयान के मुताबिक गेल और पेट्रोन संयुक्त रूप से परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय संभावनाओं का पता लगाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करेंगी। दोनों पक्ष परियोजना में निवेश और संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए अपने-अपने प्रबंधन से निवेश अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

भारत में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कारों पर ही ध्यान रहेगाः ऑडी इंडिया

- देश में फ्लग इन हाइब्रिड वाहन पेश करने की कोई योजना नहीं

नई दिल्ली (ईएमएस)। कार विनिर्माता ऑडी ने कहा कि उसका ध्यान भारत में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कारों पर ही रहेगा। कंपनी की देश में फ्लग इन हाइब्रिड वाहन पेश करने की कोई योजना नहीं है। कंपनी के एक अधिकारी ने यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च आधार और आपूर्ति श्रृंखला के मसलों के कारण इस साल भारत में लक्जरी कारों की बिक्री एक साल पहले के मुकाबले 8 से 10 फीसदी बढ़ेगी। पिछले साल यानी 2023 में इसमें 28 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और लक्जरी कार विनिर्माताओं ने अपनी 48,500 गाड़ियां बेची थीं। फिलहाल भारत में करीब 6 फीसदी इलेक्ट्रिक लक्जरी कारों की बिक्री होती है। उन्होंने कहा कि जो ग्राहक पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक कारों की ओर जा रहे हैं, उनको जीएसटी की कम दर का फायदा मिल रहा है। 1.17 करोड़ रुपये (एक्स शोरूम) से शुरू होने वाला नया मॉडल क्यू8 पेश करने के दौरान उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जब तक लक्जरी कार खंड में हमारी उपस्थिति 50 फीसदी नहीं हो जाती है तब तक हमें कम जीएसटी के रूप में सरकार से मदद की दरकार रहेगी। जहां पेट्रोल और हाइब्रिड कारों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है वहीं इलेक्ट्रिक कारों पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी देना होता है। पिछले महीने ऑडी की प्रतिद्वंद्वी बीएमडब्ल्यू समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों पर प्रोत्साहन के लिए बात की थी। बीएमडब्ल्यू समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा था कि मजबूत हाइब्रिड अथवा फ्लग इन हाइब्रिड कारें कार्बन उत्सर्जन कम करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती हैं मगर देश को कम कार्बन और प्रोत्साहनों के जरिये इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान देना चाहिए।

अमेरिका की आर्थिक मंदी का ग्रहण पीतल नगरी में लगा......निर्यातक दूसरे कामों से जुड़े

मुरादाबाद (ईएमएस)। मुरादाबाद पीतलनगरी हस्तशिल्प उद्योग के लिए देश-दुनिया में मशहूर है। कारोबार से शहर के छोटे-बड़े करीब 2400 निर्यातक जुड़े हैं। ये मुरादाबाद के हस्तशिल्प उद्योग को विदेश में अलग पहचान दिलाते हैं। मुरादाबाद से हर साल औसतन 8 से 9 हजार से करोड़ का निर्यात होता है। इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी अमेरिका की है। लेकिन, पिछले एक साल से निर्यात में उतार-चढ़ाव चल रहा है। अमेरिका की आर्थिक मंदी ने भी निर्यात को प्रभावित किया है। इसकारण पांच महीने में निर्यात में करीब 50 फीसदी की गिरावट आई है। गिरावट के बाद निर्यातकों ने कारोबार के दूसरे क्षेत्रों में उतरने का फैसला किया है। इसके बाद निर्यातकों ने होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से जुड़े कारोबार में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। निर्यातकों ने कारोबार मुरादाबाद के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी शुरू किया है।

दूसरे कारोबार में निवेश के लिए मुरादाबाद के निर्यातकों की पहली पसंद उत्तराखंड और नोएडा है। निर्यातकों ने देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी में स्कूल और रेस्टोरेंट खोल लिया है। इसके अलावा नोएडा में जेवर के आस-पास के इलाकों में प्रापर्टी का कारोबार कर रहे हैं। कुछ निर्यातक विदेश में भी निवेश करने लगे हैं। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ समय से निर्यात में गिरावट आई है। इसके कई कारण हैं। जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, अमेरिका में आर्थिक मंदी, कंटेनरों के रेट में तीन गुना वृद्धि, स्थानीय स्तर पर कच्चे माल में 15 फीसदी की वृद्धि एवं चीन के बंद बाजार का खुलना शामिल है।

तालिबान शासकों के कानून...... महिलाओं के बोलने पर प्रतिबंध

काबुल (ईएमएस)। तालिबान शासकों ने नए कानूनों के तहत सार्वजनिक रूप से महिलाओं के बोलने पर प्रतिबंध लगाया है। नए कानूनों के तहत महिलाओं को अब अपना चेहरा ढककर रखना होगा। कानून का पालन नहीं करने पर चेतावनी या गिरफ्तारी जैसे दंड दिए जाएंगे।

तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ये कानून लागू कर दिए गए। इसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हर समय अपने शरीर को ढकना अनिवार्य है। कपड़े पतले, छोटे नहीं होने चाहिए। जीवित व्यक्तियों की तस्वीरों के प्रकाशन पर भी प्रतिबंध है। संगीत बजाने, अकेली महिला के अकेले यात्रा करने और उन पुरुषों और महिलाओं के मिलने-जुलने पर प्रतिबंध लगाता है जो एक-दूसरे से संबंधी नहीं हैं।

पीएम मोदी की यात्रा रुस-यूक्रेन युद्ध रोकने में मददगार साबित होगीः यूएन

कीव (ईएमएस)। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे से उम्मीद लगा रखी है कि मोदी की यह यात्रा यूक्रेन-रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने में मददगार साबित होगी। यूएन चीफ के प्रवक्ता ने पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर कहा कि कई राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को इस क्षेत्र की यात्रा करते देखा है। हमें उम्मीद है कि ये सभी यात्राएं हमें करीब लाएंगी और यूएन के प्रस्तावों, अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय अखंडता के अनुरूप यह युद्ध खत्म होगा।

एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी शुक्रवारकोयूक्रेन पहुंचे, जहां उनकी राष्ट्रपति वलोडिमिरजेलेंस्की से मुलाकात हुई। उनकी यह यात्रा रूस यूक्रेन यात्रा के करीब डेढ़ महीने बाद हो रही है। रूस में भी उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की थी। उम्मीद की जा रही है कि जेलेंस्की से भी वह युद्ध के मुद्दे पर बात करेंगे। का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस के हमले के बाद से नाटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है।

भारत की ओर से रूस-यूक्रेन मुद्दे का बातचीत के जरिए हल निकालने पर जोर दिया है। मोदी की मॉस्को यात्रा के बाद भारत-रूस की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया था कि दोनों नेताओं ने बातचीत और कूटनीति के जरिए यूक्रेन के आसपास संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की अनिवार्यता पर जोर दिया है। भारत ने यूएन में रूस के आक्रमण की निंदा पर आए प्रस्ताव से दूरी बनाई और तटस्थता का परिचय दिया।

बता दें फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई बार फोन पर बात की। इस साल मार्च में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा था कि उन्होंने शांति के सभी प्रयासों और चल रहे संघर्ष को जल्द खत्म करने के लिए भारत समर्थन से अवगत कराया।

अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अनुसार पांच टेस्ट मैचों की ये सीरीज अगले साल जून से अगस्त के बीच खेली जाएगी। इसका पहला मैच 20 जून से होगा। वहीं अंतिम टेस्ट मैच 31 जुलाई से शुरू होगा। भारतीय टीम इंग्लैंड के पिछले दौरे में जीत के बेहद करीब पहुंचकर भी उसे हासिल नहीं कर पायी थी। ऐसे में इस बार उसका लक्ष्य जीतना रहेगा। भारत ने 2021 में इंग्लैंड दौरे पर 2-1 की बढ़त बना ली थी पर तब कोरोना संक्रमकण के चलते सीरीज बीच में रोक दी गयी थी। बाद में सीरीज का बाकी बचा एकमात्र मैच खेला गया, जिसे इंग्लैंड ने जीता। इस तरह सीरीज 2-2 से बराबर रही थी।

भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से ठीक पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल 2025 की रेस में सबसे आगे है और उसके खिताबी मुकाबले में पहुंचने की पूरी उम्मीदें हैं। इसके बाद इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज शुरू होगी। भारत-इंग्लैंड सीरीज 20 जून को शुरू होगी।अगर पांचवां टेस्ट मैच पांच दिन चलता है तो सीरीज 4 अगस्त को खत्म होगी। सीरीज का पहला मैच लीड्स में खेला जाएगा। दूसरा मैच बर्मिंघम और तीसरा मैच लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सीरीज का चौथा मैच मैनचेस्टर और पांचवां मैच 31 जुलाई से लंदन के ओवल में खेला जाएगा।

भारत इंग्लैंड सीरीज 2025 का कार्यक्रम इस प्रकार है :

पहला टेस्ट 20 से 24 जून लीड्स

दूसरा टेस्ट 2 से 6 जुलाई बर्मिघम

तीसरा टेस्ट 10 से 14 जुलाई लंदन

चौथा टेस्ट 23 से 27 जुलाई मैनचेस्टर

पांचवां टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त ओवल

पीएम मोदी की यात्रा ने खोले नौकरी के दरवाजे, पौलेंड ने की हेल्थकेयर की मांग

वारसॉ (ईएमएस)। पीएम नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा खत्म हो गई है और वह यूक्रेन पहुंच गए हैं। पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा खास रही है। पीएम मोदी की यह यात्रा भारतीयों के लिए अवसर के दरवाजे खोल रही है। उनकी यात्रा शुरू होने के बाद पोलिश राजनेता और यूरोपीय संसद के सदस्य डेरियस जोंस्की ने कहा था कि उनके देश को 25 हजार डॉक्टर, नर्स और हेल्थकेयर स्पेशलिस्ट की जरुरत है। पोलैंड में हेल्थकेयर वर्कर्स की यह मांग हजारों भारतीयों के लिए नौकरियों का अवसर पैदा करेगी।

उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बात करना चाहते हैं। हमें करीब 25 हजार डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जरूरत है। कुछ डॉक्टर और विशेषज्ञ पोलिश भाषा सीखना और परीक्षा पास करना चाहेंगे तो हम इसे लेकर बात कर सकते हैं, ताकि वह यहां काम कर सकें। हम आईटी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करना चाहते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और पोलैंड का पारस्परिक द्विपक्षीय व्यापार है, जिसका मूल्य करीब 6 अरब डॉलर है। यह पोलैंड को मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पोलैंड में भारतीय निवेश करीब तीन अरब डॉलर का है। जबकि भारत में पोलिश निवेश करीब एक बिलियन डॉलर है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्युटिकल्स, विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई भारतीय कंपनियां पोलैंड में काम कर रही हैं।

30 पोलिश कंपनियां भारत में व्यापार करती हैं। इनमें से कुछ ने स्वच्छता उत्पादों, कॉस्मेटिक, धातु पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण प्लांट लगाए हैं। 2019 में भारत और पोलैंड के बीच सीधी उड़ान शुरू हुई। पोलैंड में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, जिनकी संख्या करीब 25 हजार है। इनमें से पांच हजार छात्र है। पोलैंड ने 2022 में ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन से चार हजार से ज्यादा छात्रों को निकालने में मदद की थी।

अमेरिकी यात्रा पर राजनाथ....किए दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका और भारत ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता अमेरिकी रक्षा विभाग (डीओडी) और भारतीय रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान 22 अगस्त को हुआ है। अमरीकी रक्षा विभाग ने कहा कि इस समझौते से अमरीका और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपसी सहायता प्रदान करने पर सहमत हैं। यह सौदा संकट के समय काफी अहम हो जाता है, जब किसी देश की तत्काल जरूरतें होती हैं। समझौता अब दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता को बढ़ावा देगा।

रक्षा मंत्री सिंह ने बताया कि वॉशिंगटन डीसी में दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था (एसओएसए) के जरिए अमेरिका और भारत राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन देने के लिए सहमत हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग (डीओडी) ने कहा कि आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था दोनों देशों के रक्षा संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह अमेरिका-भारत रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) को मजबूत करने में भी अहम रोल निभाएगी।

इस समझौते के मुताबिक, अमेरिका रक्षा प्राथमिकता और आवंटन प्रणाली (डीपीएएस) के तहत भारत को आश्वासन प्रदान करेगा। इसके बदले में भारत औद्योगिक आधार के साथ एक तंत्र स्थापित करेगा। ये समझौते शांतिकाल, आपात स्थितियों और सशस्त्र संघर्षों में आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रक्रिया स्थापित करता है। ये समझौता रक्षा विभाग को उस देश की कंपनियों से अनुबंध करने में सक्षम बनाता है, जिसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते में एक प्रतिबद्धता है जो दोनों पक्षों को जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण आपूर्ति, खनिजों और प्रौद्योगिकियों तक अधिक तेजी से पहुंच प्रदान करती है। भारत यूएस का 18वां एसओएसए भागीदार है। भारत और अमेरिका के इस समझौते की घोषणा पिछले साल लॉयड ऑस्टिन की भारत यात्रा के दौरान अमेरिका-भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक नए रोडमैप के हिस्से के रूप में की गई थी। रक्षा मंत्री सिंह वर्तमान में 23 से 26 अगस्त तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी यह यात्रा अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर हो रही है। अपनी यात्रा के दौरान सिंह पेंटागन में अपने अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं।

शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द, उनके पूर्व मंत्री और सांसदों पर भी लटकी तलवार

ढाका (ईएमएस)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया। शेख हसीना के पासपोर्ट को रद्द करने का कदम अन्य पूर्व नेताओं को संकट में डाल दिया है। यह फैसला उसी दिन लिया गया, जब संयुक्त राष्ट्र की एक टीम यह आकलन करने ढाका पहुंची कि देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि शेख हसीना का पासपोर्ट, पूर्व सरकार के मंत्रियों और पूर्व सांसदों के पासपोर्ट को रद्द करना होगा। अंतरिम सरकार का यह फैसला भारत के लिए एक कूटनीतिक दुविधा पैदा करता है। बता दें कि पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना बांग्ला देश से भागकर भारत आ गई थी। जहां एक तरफ भारत सरकार शेख हसीना की मेज बाजी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को भी अपना समर्थन देने की पेश कश की है। बता दें कि, इस महीने की शुरुआत में छात्र हिंसा के शुरू होने के बाद शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देकर भाग गई थीं।

इससे पहले शेख हसीना की सरकार पर बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालय ने पिछले सप्ताह एक प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया था कि इस मामले में स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है कि सुरक्षा बलों ने अनावश्यक बल का इस्तेमाल किया था। मोहम्मद यूनुस ने संयुक्त राष्ट्र को आश्वासन दिया कि वे जांच में हरसंभव मदद करेंगे। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार, पूर्व कैबिनेट मंत्री और भंग राष्ट्रीय असेंबली के सभी सदस्य अपने पदों के आधार पर राजनयिक पासपोर्ट के पात्र थे। अगर उन्हें पदों से हटाया गया हो या वे सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उनके और उनके जीवनसाथी के पासपोर्ट रद्द करने होंगे। ढाका के नए अधिकारियों ने कहा कि शेख हसीना और उनके कार्यकाल के पूर्व शीर्ष अधिकारी स्टैंडर्ड पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते थे। बता दें कि बांग्लादेश की हिंसा में 450 से अधिक लोग मारे गए।

अब डोनाल्ड ट्रंप बनाम कमला हैरिस जंग आधिकारिक तौर पर कन्फर्म

शिकागो (ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति में अब डोनाल्ड ट्रंप बनाम कमला हैरिस जंग आधिकारिक तौर पर कन्फर्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेट्स की ओर से कमला हैरिस ही ताल ठोंकेंगी। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेट्स की उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया। कमला हैरिस रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि यदि वह राष्ट्रपति चुनी जाती है तो वह यूक्रेन और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। बता दें कि हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारतीय थीं और उनके पिता डोनाल्ड जैस्पर हैरिस जमैका के नागरिक थे। अगर हैरिस निर्वाचित होती हैं, तो वह अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी।

भारतीय-अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस ने शिकागो में गुरुवार की रात 'डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन' के दौरान उम्मीदवारी स्वीकार की और इसी के साथ वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की दूसरी महिला नेता बन गईं। उन्होंने कहा, 'लोगों की ओर से, प्रत्येक अमेरिकी की ओर से, चाहे वह किसी भी पार्टी, जाति, या भाषा से संबंध रखता हो, मेरी मां की ओर से और उन सभी लोगों की ओर से जिन्होंने ऐसे अमेरिकियों की ओर से अपनी असंभव यात्रा शुरू की, जिनके साथ मैं बड़ी हुई, जो कड़ी मेहनत करते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं और एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं, उन सभी की ओर से जिनकी कहानी पृथ्वी के सबसे महान राष्ट्र में ही लिखी जा सकती है, मैं उम्मीदवारी स्वीकार करती हूं।' शिकागो के 'यूनाइटेड सेंटर' में उम्मीदवारी स्वीकार करने के लिए मंच पर आईं कमला हैरिस (59) ने कहा कि उनके लिए असंभव यात्राएं कोई नयी बात नहीं है। कमला हैरिस ने कहा कि उनके प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप गैर-गंभीर व्यक्ति नहीं हैं और उन्हें फिर से राष्ट्रपति बनाने के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। इस दौरान उन्होंने सभी अमेरिकियों की राष्ट्रपति बनने की कसम खाई। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा और कहा कि वह सीरियस आदमी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी राष्ट्रपति बनेंगी, जो देश के लोगों को एकजुट करेंगी। उन्होंने कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव एक नया रास्ता बनाने का मौका है। वह किसी एक पार्टी या गुट के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिकियों के रूप में आगे बढ़ने का मौका है। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव है। चुनाव में कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार एवं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन से पहले दो महत्वपूर्ण बैठक की

नई दिल्ली (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन से पहले दिल्ली में दो महत्वपूर्ण बैठक की। इन बैठकों में राज्य के समीकरण और तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

पहली बैठक सुबह अमित शाह के आवास पर हुई। जिसमें राज्य के चुनाव प्रभारी राम माधव, जी. किशन रेड्डी सहित अन्य नेता शामिल हुए। इसके बाद शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कोर ग्रुप की बैठक हुई। सीईसी की बैठक भी जल्द होने वाली है।

जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सभी कोर ग्रुप के सदस्य, जिनमें केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी जी. किशन रेड्डी और राम माधव, राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा जम्मू-कश्मीर प्रभारी तरुण चुघ, सह-प्रभारी आशीष सूद, जम्मू के सांसद जुगल किशोर शामिल हुए। बैठक में प्रदेश महासचिव (संगठन) अशोक कौल, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, केंद्रीय मंत्री और जम्मू से सांसद जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी जल्द सीईसी में राज्य की 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगी। यह चुनाव कई पहलुओं खासकर राज्यों की सुरक्षा के लिहाज से अहम है। वरिष्ठ नेता के अनुसार, जम्मू क्षेत्र भाजपा के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या यहां बढ़कर 43 हो गई है। पार्टी जम्मू में अपना पूरा जोर लगाएगी। राम माधव को केंद्र शासित प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए भाजपा चुनाव प्रभारी बनाया गया है। माधव ने 2014 में भाजपा-पीडीपी के बीच गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

केंद्र सरकार ने एम्स समेत अन्य शीर्ष संस्थानों को दीक्षांत समारोहों में भारतीय परिधान अपनाने को कहा

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने एम्स समेत अन्य शीर्ष संस्थानों को दीक्षांत समारोहों में भारतीय परिधान अपनाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने दीक्षांत समारोहों में ब्रिटिश काल से चले आ रहे काली टोपी और काले लिबास का उपयोग न करें।

माना जा रहा है कि मंत्रालय द्वारा उठाया गया यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रेखांकित "पंच प्रण" संकल्पों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश काल से जुड़ी विरासत को छोड़ना और उनकी जगह भारतीय परंपराओं को अपनाना है।

23 अगस्त को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि दीक्षांत समारोह के दौरान काली टोपी और काले लिबास पहनने की मौजूदा प्रथा ब्रिटिश काल में भारत में भी शुरू की गई थी, जो मध्य युग के दौरान यूरोप से आई है। मंत्रालय ने संस्थानों से दीक्षांत समारोहों के लिए नए भारतीय पोशाक डिजाइन करने का आग्रह किया है, जो उस राज्य की स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता हो, जहां वह संस्थान स्थित है। चिट्ठी में कहा गया है कि वर्तमान परंपरा ब्रिटिश उपनिवेशकाल की याद दिलाता है, जिसे खत्म करने की जरूरत है।

दूध की पैकेजिंग से हटेंगे ए1 और ए2 लेबल

- एफएसएसएआई ने कहा- ये भ्रामक, ई-कॉमर्स कंपनियां और फूड बिजनेस 6 महीने के भीतर हटाएं

मुंबई (ईएमएस)। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने ई-कॉमर्स कंपनियों और फूड बिजनेसेस को मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग से ए1 और ए2 लेबलिंग हटाने का आदेश दिया है। फूड रेगुलेटर ने इस तरह के दावे को भ्रामक कहा है। एफएसएसएआई ने अपने आदेश में कहा कि ये दावे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए रेगुलेटर इस विसंगति को हटाना चाहता है। इन्हें ये रेगुलेटर ने बिजनेसेस को लेबलिंग हटाने के लिए 6 महीने का समय दिया है और कंपनियों को इसका पालन करना होगा... [illegible]

मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट्स पर ए1 और ए2 टाइप लेबल का मतलब दूध में मौजूद बीटा-कैसिइन प्रोटीन के केमिकल स्ट्रक्चर से जुड़ा है। यह दूध देने वाले पशु के ब्रीड से जुड़ा होता है। बीटा कैसिइन दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जानेवाला प्रोटीन है और इसमें अमीनो एसिड का बेहतर न्यूट्रिशनल बैलेंस होता है। रेगुलेटर ने इस लेबलिंग के 6 महीने के भीतर हटाने को कहा है।

आमतौर पर ए2 मिल्क मूल रूप से भारतीय नस्ल की गायों से आता। ये प्रोटीन में रिच होते हैं। इनमें लाल सिन्धी, साहीवाल, गिर, देवनी और थारपारकर जैसी कैटेगरी शामिल हैं।

सितंबर माह से शुरू हो जाएगी जनगणना

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार 1 सितंबर से जनगणना का कार्य शुरू कर सकती है। इसके लिए सितंबर माह से लेकर दिसंबर 2024 तक के आंकड़े एकत्रित कर जनगणना की जाएगी। सरकार ने अभी तक इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनगणना के आंकड़े किस तरह से एकत्रित किए जाएं। इसका फॉर्म तैयार कर लिया गया है। इसमें जातिगत जनगणना को शामिल करना है, या नहीं। इस पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।

वर्तमान नियमों के अनुसार यह जनगणना 2021 में की जानी थी। उस समय कोविड के कारण इस जनगणना को टाल दिया गया था। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है। जनगणना का चक्र बदला जाए। यदि ऐसा हुआ तो जनगणना 2025 2035 और 2045 के नए चक्र में कराई जाएगी। 1881 से भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है।

जनगणना के आंकड़ों को जुटाने के लिए फील्ड में सरकारी कर्मचारी जाते हैं। प्रत्येक परिवार की जनसंख्या के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर भी जानकारी एकत्रित की जाती है। इसमें 4 से 6 माह का समय लगता है। जनगणना एक्ट 1948 के अनुसार अभी एससी और एसटी वर्ग की जनगणना का प्रावधान है। पिछड़े वर्ग की जनगणना करना है,तो इसका प्रावधान करने के लिए इसमें संशोधन लाना पड़ेगा। सभी जानकारी को एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित करने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है।

जातियों के आधार पर जनगणना अभी तक की जानकारी के अनुसार पिछड़े वर्ग की 2650 जातियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 एससी और 748 एसटी वर्ग की जातियां थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देशभर में 4668 जातियों के लोग एसटी / एससी और पिछड़े वर्ग की जातियां हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग की जातियां अलग हैं।

उत्तर-मध्य गुजरात में मूसलाधार बारिश, देहगाम में 1 घंटे में 3 इंच बारिश, हर तरफ पानी भर गया

अहमदाबाद,23 अगस्त

मौसम विभाग ने 28 अगस्त तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि दक्षिण, मध्य, उत्तर गुजरात समेत सौराष्ट्र के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है. भारी से बहुत भारी बारिश के कारण राज्य के कई इलाके पानी से भर गए हैं और नदियां और नहरें उफान पर हैं. राज्य में उत्तर और मध्य गुजरात समेत सौराष्ट्र पर मेघराज की मेहरबानी हुई है, जबकि अरावली, मोडासा, गांधीनगर, देहगाम, बोटाद, राणपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है. जबकि देहगाम में एक घंटे में तीन इंच बारिश हुई है।

लंबे अंतराल के बाद राज्य में बारिश की दस्तक हुई है, राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई, जबकि गांधीनगर के देहगाम सहित तालुका में गरज के साथ बारिश हुई। जिसमें देहगाम में एक घंटे में तीन इंच बारिश हुई, नंदोल रोड, पूर्णिमा स्कूल के पास, नेहरू चौक, पथिकाश्रम, अनुराधा सोसायटी, हरिओम सोसायटी समेत कई इलाकों में पानी भर गया है और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है.

मौसम विभाग की ओर से राज्य में उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जबकि अरावली जिले के मालपुर, मेघराज, रेलावाड़ा, इसरी, जीतपुर, शक्तिनगर, जनतानगर, धनसुरा के कंजरी कंपा सहित मोडासा के टिंटोई में अच्छी बारिश हुई है। जिसमें मोडासा के सरदोई में लंबे समय बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और सरदोई में मेघराजा की मेहरबानी से किसानों में खुशी का माहौल है. वहीं भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया और लोगों को आफत का सामना करना पड़ा.

राज्य में जहां मेघराज की मेहरबानी हुई है, वहीं बोटाद और राणपुर समेत कई इलाकों में गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। जिसमें बोटाद और राणपुर समेत कुछ निचले इलाकों में बाढ़ के कारण आपदा का सामना करना पड़ा।

24 अगस्त को मेघराज उत्तर, दक्षिण, पूर्व और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में धूम मचाएंगे। जिसमें दक्षिण गुजरात के दाहोद, पंचमहल, आनंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा, तापी, सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग जिलों के छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। जबकि बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, अरावली, पाटन, गांधीनगर, महिसागर, खेड़ा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, बोटाद, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

भारी बारिश के बाद 25 अगस्त को बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, खेड़ा, पंचमहल, आनंद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच और नर्मदा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, बोटाद, भावनगर, राजकोट, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड जिलों में भारी बारिश के कारण येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा कच्छ, मोरबी, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर जिलों में कोई चेतावनी घोषित नहीं की गई है.

एएमसी अग्निशमन विभाग की सख्त कार्रवाई, फर्जी प्रायोजन पर 9 अधिकारी निलंबित

अहमदाबाद, 23 अगस्त

ँश्ण अग्निशमन विभाग के 9 अधिकारी निलंबितः ँश्ण ने फर्जी स्पॉन्सरशिप के मामले में 9 अधिकारियों को नोटिस भेजा. हालांकि, इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और स्पॉन्सरशिप की जानकारी झूठी होने के बाद एएमसी ने 9 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस मामले में आगे की जांच की जाएगी.

फर्जी प्रायोजन के जरिए एएमसी में नौकरी करने वाले 9 अधिकारियों ओम जड़ेजा, आसिफ शेख, सुधीर गढ़वी, शुभम खड़िया, अभिजीत गढ़वी, मेहुल गढ़वी, अनिरुद्ध गढ़वी, कैजाद दस्तूर, इनायत शेख को निलंबित कर दिया गया है।

अहमदाबाद मुन. एन.एफ.5.सी., नागपुर में उच्च और आपातकालीन सेवा विभाग में सेवा करते हुए ओम जड़ेजा, आसिफ शेख, सुधीर गढ़वी, शुभम खड़िया, अभिजीत गढ़वी, मेहुल गढ़वी, अनिरुद्ध गढ़वी, कैज़ाद दस्तूर, इनायत शेख सहित 9 अधिकारियों द्वारा अनधिकृत/झूठे प्रायोजन के माध्यम से निगम में गलत तरीके से प्रवेश लेकर शैक्षणिक योग्यता हासिल करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर विजिलेंस जांच और औद्योगिक संबंध लेखा की विभागीय जांच में अपराध सिद्ध हुआ. आयुक्त द्वारा समाप्त क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उनका दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया.

गुजरात में ड्रग माफिया पर कार्रवाईः एक साल में 5640 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त

गांधीनगर,23 अगस्त

गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है. विधानमंडल सत्र के आखिरी दिन आज 116 के नोटिस पर ड्रग्स जब्ती पर चर्चा, सदन में ड्रग्स के मुद्दे पर बहस शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया. हर्ष सांघवी ने सदन को पिछले एक साल में गुजरात से जब्त की गई ड्रग्स की मात्रा की जानकारी दी.

पिछले15 दिनों में गुजरात पुलिस द्वारा राज्य के कच्छ, वलसाड, नवसारी जिलों के तट से 850 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई है. जिसके लिए गुजरात पुलिस और गुजरात एटीएस टीम बधाई की पात्र है. पिछले एक साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत 317 अपराध दर्ज किए गए हैं और कुल 431 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अनुमानित 5640 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है.

वर्ष-2024 में गुजरात एटीएस के माध्यम से रु. 427 करोड़ की करीब 61 किलो ड्रग्स जब्त की गई है. गुजरात पुलिस ने समुद्री इलाके में स्थित छोटे-बड़े लैंडिंग पॉइंट्स पर 178 करोड़ की अवैध ड्रग्स भी पकड़ी है. हाल ही में ड्रग आरोपी की गृह मंत्री हर्ष सांघवी के साथ तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसके बारे में गृह मंत्री ने सदन में बयान देते हुए कहा था, ''ड्रग्स के आरोपी की मेरे साथ खड़े होने की तस्वीरें वायरल हुईं. अगर मेरे पास फोटो भी है तो भी पुलिस ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी. प्रदेश की जनता को यह समझ लेना चाहिए कि पुलिस नशे में लिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी। मेरे पास फोटो होने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई की है. आज सदन में नशीली दवाओं पर किसी भी बहस में, मैंने अध्यक्ष से बहस का सीधा प्रसारण करने का अनुरोध किया है।

सरकार ने गुजरात के तट पर नशीली दवाओं के पाए जाने का कारण बताते हुए कहा कि गुजरात पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफी को रोक दिया जाता है, यही कारण है कि गुजरात पुलिस की नाव के आते ही दवाओं के इन पैकेटों को समुद्र में फेंक दिया जाता है। देखा गया। गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर समय-समय पर एनसीओआरडी बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि नशीली दवाओं के भंडाफोड़ अभियान में लगी विभिन्न एजेंसियां एक-दूसरे के साथ समन्वय कर सकें और राज्य भर में एक टीम के रूप में काम कर सकें।

गुजरात सरकार ने फसल क्षति के लिए 350 करोड़ के कृषि सहायता पैकेज की घोषणा की

गांधीनगर,23 अगस्त

गुजरात में जुलाई महीने में 9 जिलों में भारी बारिश से हुई फसल क्षति को लेकर कृषि मंत्री ने विधानसभा में 350 करोड़ के सहायता पैकेज की घोषणा की है. जिसमें सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लास शामिल हैं। कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने सहायता पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा. विधानसभा के नियम 44 के तहत सदन में कृषि सहायता पैकेज की घोषणा की गई है.

विधानसभा भवन में किसानों के लिए कृषि राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि जुलाई 2024 के दौरान गुजरात के कुछ जिलों में भारी बारिश से किसानों की कृषि और बागवानी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। ऐसे गंभीर आर्थिक नुकसान वाले किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा 350 करोड़ रुपये के कृषि राहत पैकेज की घोषणा की गई है।

राहत पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, आनंद, भरूच के कुल 45 तालुकाओं में 4,06,892 हेक्टेयर क्षेत्र भारी बारिश से प्रभावित हुआ था. , सूरत, नवसारी और तापी जिले। इस प्रभावित क्षेत्र में 272 टीमें गठित कर विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया है. जिसके आधार पर 1.50 लाख से अधिक प्रभावित किसानों को सहायता दी जाएगी.

मंत्री राघवजी पटेल ने किसानों को नियमानुसार सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंडों के बारे में बात करते हुए कहा कि प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के मानदंडों के अनुसार फसल नुकसान के लिए सहायता दी जाएगी.

केवल साइबर फ्रॉड में ट्रांसफर किए गए पैसों पर रोक लगाने की नीति बनाकर गुजरात पूरे देश के लिए एक मॉडल राज्य बन गया हैः गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष सांघवी

गांधीनगर,23 अगस्त

विधानसभा सदन में बैंक खातों को फ्रीज करने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष सांघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के मार्गदर्शन में फ्रीजिंग की नीति बनाकर गुजरात पूरे देश के लिए एक मॉडल राज्य बन गया है। साइबर फ्रॉड में रकम बैंक खातों के बजाय ही ट्रांसफर की गई। गृह विभाग के निर्देश पर गुजरात पुलिस की साइबर सेल ने साइबर अपराध के शिकार मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए दिन-रात काम करते हुए केवल 20 दिनों में 2.58 लाख से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। यानी पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में बैंक खातों को अनफ्रीज करने में गुजरात पहले स्थान पर है।

इतना ही नहीं, साल-2024 में 85.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई, जिसमें से पुलिस 66.15 करोड़ रुपये की रकम वापस कराने में सफल रही है. अभी भी शेष राशि वसूलने का प्रयास कर रहे हैं, वसूली दर को 100 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।

नई नीति के अनुसार, पूरे खाते के बजाय, धोखाधड़ी में शामिल केवल विशिष्ट राशि को फ्रीज किया जाएगा। इन खातों को अनफ्रीज करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन एनसीसीआरपी पोर्टल पर लेयर वाइज रिपोर्ट में बैंक के नाम और उस बैंक खाते में विवादित राशि के साथ बैंक खाते के खिलाफ रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही थी। इसलिए उक्त बैंक खाते को अनफ्रीज करने में देरी हुई, बाद में इस संबंध में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली (घ्4ण) के साथ आवश्यक समन्वय प्राप्त किया गया, निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई प्राप्त की गई और इस जानकारी के साथ रिपोर्ट को सफलतापूर्वक अद्यतन किया गया है एनसीसीआरपी पोर्टल पर और अब इस आवश्यक सुधार के साथ एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

मंत्री ने आगे बताया कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है. दुनिया भर के तमाम विकसित देश भी इसका सामना कर रहे हैं. साइबर जालसाजों के पास एक कार्यप्रणाली होती है, जिसके अनुसार धोखाधड़ी में प्राप्त राशि तुरंत अलग-अलग लोगों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कई निर्दोष नागरिकों के खातों में पैसा जमा किया जाता है। नियम के मुताबिक इस खाते को फ्रीज कर दिया गया, जिससे उस मासूम की बचत भी फ्रीज हो गई.

जिसके चलते नीति में बदलाव का अहम फैसला लिया गया है और इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जो साइबर जालसाजों की चाल में फंस गए थे और डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर धोखाधड़ी का शिकार हो गए थे या फिर अनजाने में इस तरह के जाल में फंस गए थे. जाल। नई नीति के मुताबिक, अब बैंक खाते की कुल रकम की बजाय धोखाधड़ी में शामिल रकम ही जब्त की जाएगी। यानी अब पूरे खाते की बजाय धोखाधड़ी से जुड़ी खास रकम ही फ्रीज की जाएगी. यह निर्णायक कदम नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजकोट में लोक मेले पर विवाद, सवारी शुरू होने पर असमंजस

राजकोट, 23 अगस्त

सौराष्ट्र का सांस्कृतिक समूह लोक मेला सिस्टम के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है. राजकोट (ँरव्दू) में सरकारी गाइड लाइन के मुताबिक नियम पत्र मिलने के बाद ही बड़ी सवारी वालों को लॉट आवंटित किया जाता था. लेकिन देर रात तक बड़े सवारियों ने किसी प्रकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। जिसके बाद कलेक्टर प्रभाव जोशी ने नियमानुसार सवारी चलाने की अनुमति नहीं दी।

वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के कुछ नेता सिस्टम को गुमराह करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. लोक मेला का उद्घाटन अब कुछ ही घंटे दूर है। मैकेनिकल सवारी से शुरू हुआ विवाद और असमंजस अब भी जारी है. नींव और मिट्टी की रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इन सबके बीच एक विभाग ऐसा भी है जिसकी राय और सर्टिफिकेट के बाद ही सवारी शुरू की जा सकती है। उस विभाग में अभी तक एक भी उचित सवारी ने अनुमोदन के लिए आवेदन नहीं किया है। आग लगने की घटना के बाद टीआरपी ने मेले में लोगों की सुरक्षा को लेकर एसओपी बनाई है. जिसमें हर बड़ी सवारी में फाउंडेशन को अनिवार्य कर दिया गया है.

उधर, मेले में सभी राइडिंग प्लॉट एक साथ लेने वाले भाजपा नेताओं का कहना है कि मिट्टी की रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसलिए राइडिंग में फाउंडेशन की कोई जरूरत नहीं है। उधर, सिस्टम का कहना है कि उन्हें रिपोर्ट नहीं दी गई है, लेकिन एसओपी के मुताबिक काम होगा। सवारी को मंजूरी देना पुलिस की जिम्मेदारी है. ऐसा कहकर प्रशासन ने पुलिस को भी इसमें शामिल कर लिया है.

सौराष्ट्र की उत्सवप्रिय जनता असमंजस में है. पूरा मामला अब गुजरात हाई कोर्ट में चला गया है. ऐसा लग रहा है कि फैसला आज दोपहर को आ जाएगा. जिसमें मेला तो लगेगा लेकिन बड़ी सवारी शुरू नहीं हो सकेगी. निजी मेलों में भी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा, सभी मेलों में बड़ी सवारी निकलेगी या नहीं, इस पर आज दोपहर फैसला लिया जाएगा.

भाजपा सरकार में गुजरात टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय औसत से पीछे है : कांग्रेस

अहमदाबाद (ईएमएस) मॉडल राज्य नंबर वन भाजपा सरकार का दावा करती है, जबकि गुजरात टीकाकरण के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों और राष्ट्रीय औसत से पीछे है। गुजरात में टीकाकरण कवरेज 76.3 फीसदी है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत 76.4 प्रतिशत होने उल्लेख करते हुए गुजरात कांग्रेस के मीडिया संयोजक एवं प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि एनएचएफएस-5 के नतीजों के मुताबिक 12 महीने की उम्र के बच्चों के टीकाकरण पर रिपोर्ट में बच्चों के टीकाकरण में असमानता बताई गई है। डीटीपी3 के संदर्भ में - डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस वैक्सीन स्पष्ट रूप से देश में 76.4 प्रतिशत औसत टीकाकरण कवरेज की तुलना में गुजरात में केवल 76.3 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज है, यानी गुजरात के मुकाबले जम्मू और कश्मीर 86.2 प्रतिशत, राजस्थान 80.4 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 79.7 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 77.10 प्रतिशत हो चुका है। राष्ट्रीय परिवार एवं कल्याण सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट में टीकाकरण कवरेज में 90.5 प्रतिशत के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य उडीसा है। जबकि गुजरात को स्वास्थ्य क्षेत्र में 21वीं रैंक के साथ आखिरी राज्य घोषित किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 171 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2828 उप स्वास्थ्य केंद्रों की लंबे समय से कमी है। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 185, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 162, उप जिला अस्पतालों में 256 और जिला अस्पतालों में 173 डॉक्टरों के पद लंबे समय से खाली हैं। राज्य के 344 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2064 विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता के मुकाबले केवल 206 डॉक्टर ही डयूटी पर हैं जबकि 1858 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद लंबे समय से खाली हैं। यानी 90 फीसदी से ज्यादा पद खाली हैं। भाजपा राज में उद्योगपति, करीबी तो स्वस्थ हो गये, गरीब-आम और मध्यम वर्ग का स्वास्थ्य संकट में पड़ गया है। गतिशील, प्रगतिशील और वायब्रेंट होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार के खराब प्रदर्शन का सीधा असर गुजरात के आम-मध्यम वर्ग के नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ा है।

जन्माष्टमी पर जामनगर मंडल द्वारा अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी

जामनगर (ईएमएस) देवभूमि द्वारका में जन्माष्टमी उत्सव के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आनेवाले श्रद्धालुओं के लिए जीएसआरटीसी के जामनगर मंडल द्वारा अतिरिक्त बसों का संचालन का आयोजन किया गया है। द्वारका जाने वाले श्रद्धालुओं को आने-जाने में कोई परेशानी न हो और अच्छी सुविधा मिले इसके लिए जामनगर जीएसआरटीसी की ओर से बसों का खास प्रबंध किया गया है। जन्माष्टमी महोत्सव-2024 के मद्देनजर पूरे गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि द्वारका पहुंचेंगे। जिसे देखते हुए 25 से 27 अगस्त 2024 तक यात्रियों की आवाजाही के लिए जीएसआरटीसी के जामनगर मंडल द्वारा अतिरिक्त संचालन की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत 25 से 27 अगस्त तक श्रद्धालु जामनगर डिपो से अतिरिक्त बसों में अग्रिम बुकिंग कर सकेंगे और यदि एक ही समूह के 51 से अधिक यात्री समूह बुकिंग करते हैं, तो एसटी निगम द्वारा अतिरिक्त बसों की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिसमें जामनगर से द्वारका, राजकोट, मोरबी, अहमदाबाद, जूनागढ़ और द्वारका से पोरबंदर, हर्षद, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, सोमनाथ सहित जामनगर खंड की 25 बसें अतिरिक्त यातायात को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएंगी।

आज विश्व गुजराती भाषा दिवस

गांधीनगर (ईएमएस) गुजराती साहित्य के आदि कवि 'नर्मद' के जन्मदिवस, 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गुजरात की गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में इस वर्ष एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इसके अंतर्गत हमारी अनमोल विरासत से जुड़े गुजरात के मध्यकालीन कवियों की पांडुलिपियों एवं रचनाओं को संरक्षित करने के लिए भक्त कवि नरसिंह मेहता अंतराष्ट्रीय संशोधन केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

जन्माष्टमी को लेकर ओखा-बेट द्वारका के बीच बने सुदर्शन सेतु पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध

देवभूमि द्वारका (ईएमएस) आगामी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए देवभूमि द्वारका के ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने एक अधिसूचना जारी कर 22 अगस्त से 27 अगस्त 2024 तक सुदर्शन सेतु पर भारी वाहन और प्राइवेट बसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था समेत सरकारी वाहनों पर लागू नहीं होगा। दरअसल देवभूमि द्वारका में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। खासकर जन्माष्टमी के अवसर पर यह संख्या लाखों हो जाती है। देवभूमि द्वारका आनेवाले श्रद्धालु बेट द्वारका भगवान के दर्शन करने जरूर जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सुदर्शन सेतु पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगने के बाद अब प्राइवेट बसें सुदर्शन सेतु पर प्रवेश नहीं कर सकेंगी। देवभूमि द्वारका और बेट द्वारका सालाना 20 लाख से भी अधिक श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते हैं। देवभूमि द्वारका से बेट द्वारका जाने वाले श्रद्धालु पहले नाव के जरिए समुद्र पार करते थे। लेकिन अब सुदर्शन सेतु बन जाने से श्रद्धालु वाहन के जरिए बेट द्वारका जाते हैं। बता दें कि गत फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले करीब ढाई किलोमीटर लंबे केबल स्टेयड ब्रिज का उदघाटन किया था। इस ब्रिज का नाम सुदर्शन सेतु रखा गया है। यह ब्रिज भारत का सबसे लंबे केबल स्टेयड ब्रिज है। यह सेतु देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का हिस्सा है और यह रु. 980 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है। जिसमें दोनों तरफ फुटपाथ पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे एक मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसके अलावा सुदर्शन सेतु के दोनों किनारों पर श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेश और श्रीकृष्ण की विभिन्न छवियां चित्रित की गई हैं।

बहुचराजी माता मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रथम चरण के कार्य का शास्त्रोक्त विधि से शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने बहुचराजी माता के मंदिर में दर्शन तथा पूजा-अर्चना कर जनता के सुख-स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा जिले में बेचराजी स्थित सुप्रसिद्ध यात्राधाम बहुचराजी में बहुचर माता के मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रथम चरण के कार्य का शुक्रवार को शास्त्रोक्त विधि से शिलान्यास किया। भूपेन्द्र पटेल ने बहुचर माता के दर्शन कर धन्यता की अनुभूति की। उन्होंने बहुचर माता की पूजा-अर्चना कर जनता के सुख-स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की।

इस अवसर पर पर्यटन विभाग तथा गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड (जीपीवायवीबी) द्वारा बहुचराजी मंदिर पुनर्निर्माण का समग्र मानचित्र मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर सहित पुनर्निर्माण के तीनों चरणों में किए जाने वाले समग्र कार्यों का सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर में उपस्थित दर्शनार्थियों तथा स्थानीयों का उत्साहपूर्ण अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत, पूर्व उप मुख्यमंत्री नीतिन पटेल, पूर्व मंत्री रजनी पटेल, राज्यसभा सांसद मयंक नायक, लोकसभा सांसद हरिभाई पटेल, विधायक सुखाजी ठाकोर, अग्रणी गिरीशभाई राजगोर, वर्षाबेन दोशी, यज्ञेश दवे, पर्यटन विभाग के सचिव राजेन्द्र कुमार, जीपीवायवीबी की सचिव श्रीमती एस. छाकछुआक, मेहसाणा की प्रभारी जिला कलेक्टर डॉ. हसरत जैस्मीन आदि भी उपस्थित रहे। यहाँ उल्लेखनीय बहुचराजी माता मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रथम चरण के कार्य के अंतर्गत 76.51 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का पुनर्निर्माण कर शिखर की ऊँचाई 86 फीट 1 इंच तक बढ़ाई जाएगी।

इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना के आरोपी तथ्य पटेल एक साल बाद मिली एक दिन की जमानत

अहमदाबाद (ईएमएस) पिछले साल जुलाई में शहर के एसजी हाईवे स्थित इस्कॉन ब्रिज पर तेज रफ्तार जगुआर चलाकर 9 लोगों की जान लेने वाले तथ्य पटेल को करीब एक साल बाद एक दिन की जमानत मिली है। दरअसल तथ्य पटेल ने अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी। जिसे कोर्ट में मंजूर कर लिया और उसे अपने दादा के अंतिम संस्कार के बाद वापस जेल भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि 19 जुलाई 2023 को अहमदाबाद के एसजी हाईवे स्थित इस्कॉन ब्रिज पर तथ्य पटेल ने तेज रफ्तार जगुआर कार चलाकर कई लोगों को बुरी तरह रौंद दिया था। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि घटना के वक्त जगुआर कार की प्रति घंटे 150 की रफ्तार से दौड़ रही थी। जांच में यह भी पता चला कि तथ्य पटेल ड्रींक कर कार चला रहा था। रईशजादे तथ्य पटेल के नशे और तेज रफ्तार के शौक ने 9 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस मामले में पिछले 13 महीने से जेल में बंद तथ्य पटेल ने कई बार जमानत के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। लेकिन हर बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई। 13 महीनों में पहली बार तथ्य पटल को दादा जी के अंतिम संस्कार के लिए जमानत मिली। अहमदाबाद जिला सत्र न्यायालय ने तथ्य पटेल को शर्तों के साथ जमानत दी है। जिसके मुताबिक तथ्य को पुलिस सुरक्षा में तथ्य पटेल को अंतिम संस्कार ले जाएगा और उसके बाद उसे वापस जेल भेजा जाएगा।

निजी विश्वविद्यालयों को अब सरकार का समर्थनः विधानसभा में विधेयक पारित

अहमदाबाद, 23 अगस्त

गांधीनगरः गुजरात विधानसभा के तीन दिवसीय संक्षिप्त सत्र का आज आखिरी दिन था. आखिरी दिन भी सरकार की ओर से एक अहम बिल लाया गया. आज सरकार ने राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के नाम, स्थान और अधिकार क्षेत्र में बदलाव जैसे मामलों में संशोधन लागू करने की प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सदन में पारित कर दिया है।

विधानसभा सत्र में शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने विधेयक पेश किया. इस संशोधन विधेयक के लागू होने से विश्वविद्यालय का नाम और स्थान बदलने जैसे मामलों में संशोधन के लिए विधानसभा में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस अधिनियम को गुजरात निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2024केरूप में गुजरात निजी विश्वविद्या लय विधेयक, 2009 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है।

गुजरात निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 ठप्रिंसिपल एक्टठ की धारा -10 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी भी मौजूदा कॉलम या नोट को बदल सकती है। ऐसा संशोधन प्रावधान लाया गया है.राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के गुणात्मकऔरउद्योग-प्रासंगिक प्रावधान के लिए राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके कामकाज को विनियमित करने के लिए गुजरात निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया है। जिसके अनुसार वर्तमान में राज्य में कुल 65 निजी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। गुजरात के संबद्ध कॉलेजों में 1833और गुजरात के विश्वविद्यालयों में 2071 यानी कुल 3904 विदेशी छात्र गुजरात में पढ़ रहे हैं।

प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड का आईपीओ मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 को खुलेगा

प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरोंका आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 को खुलेगा। कुलऑफरस इजमें रु.12,914 मिलियन तकका एकनयानिर्गमऔर 34,200,000 इक्विटी शेयरों तक का ऑफर फॉर सेल शामिलहै।

एंकर निवेशक बोली की तिथि 26 अगस्त,2024है और ऑफर 29 अगस्त, 2024 को बंद होगा। ऑफर का प्राइसबैंड रु. 427 से रु. 450 प्रति इक्विटीशेयरहै। न्यूनतम 33 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 33 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकती हैं।

कंपनी ने फ्रेश इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग अपना सहायक कंपनी प्रीमियर एनर्जीज ग्लोबल एनवायरन मेंट प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के लिए करने का प्रस्ताव किया है, ताकि हैदराबाद, तेलंगाना, भारतमें 4 गीगावा टसोलरपीवीटॉपकॉनसेलऔर 4 गीगावाटसोलर पीवी टॉपकॉन मॉडयूल विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए आंशिक वित्तपोषणकियाजासके, जिसकाअनुमानितमूल्य रु.9,686.03 मिलियनहैऔरजिसेवित्तवर्ष 2025 औरवित्तवर्ष 2026 में लगाया जाएगा। इसके अलावा अन्य राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए कियाजाएगा।

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (बीएसई) औरनेशनल स्टॉकएक्सचेंजऑफइंडियालिमिटेड (एनएसई) जैसे स्टॉक एक्सचेंजोंमें सूचीबद्ध करने का प्रस्तावहै। प्रस्ताव के प्रयोजनोंके लिए, नामित स्टॉक एक्सचेंज बीएसई होगा।

कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड इस प्रस्ताव के बुक रनिंगलीड मैनेजर हैं।

बेटी के चले जाने से हताश मां ने गटगटाया जहर

वडोदरा (ईएमएस) डभोई में रहने वाले एक मजदूर की बेटी हाल ही मेंअपनेप्रेमी के साथ रहने के लिए चली गई थी। इस घटना के बाद बेटी की मांकाफी परेशान रहने लगी। लगातार चिंता में रहनेवाली माता ने जहर गटगटा लिया। हांलाकि उसे बचा लिया गया है। बाद में महिला ने चाणोद पुलिस स्टेशन में एक संज्ञेय शिकायत दर्ज कराई। जिसके आधार पर पुलिसने मामले जांच की। 45वर्षीयरमीलाबेनरतनसिंह भीखूसिंह राजपूत अपनेपरिवार के साथ वडोदरा के पास डभोई के तेंतलाओ में परिवार केसाथरहती हैं। उनकी बेटी का राहुल नाम के युवक से प्रेम संबंध था। हाल ही में रमीलाबेन की बेटी अपने प्रेमीकेसाथ रहने चली गई। इस घटना के बाद बेटी की मां लगातार चिंता में रहने लगी। मां का मानना था कि बेटी केकदमोंने उसे समाज में बदनाम करने के लिए छोड़ दिया है। यही बातें लगातार उसके दिमाग में घूमने लगी। लगातार लगातार बदनामी की आशंका से घिरी रमिलाबेन ने 21 अगस्त को जहर निगल लिया।

पश्चिम रेलवे-अहमदाबाद

बिजली विभाग (निर्माण)

ई-निविदा सं. ईएल/सी/एडीआई/टीआरडी/33/2024-25. (1) कार्य का नाम उसके स्थान सहित: पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल में Y कनेक्शन सहित गांधीधाम (GIM) - आदिपुर (AI) के बीच चौगुनी लेन करने के संबंध में आदिपुर अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रवेश (20 TKM) का प्रावधान कराने हेतु गांधीधाम-आदिपुर अनुभाग में Y कनेक्शन सहित हाई राईज 25 KV AC OHE की डिजाईन, आपूर्ति, निर्माण, परिक्षण और कमीशनींग करने का कार्य । (2) कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 8,38,54,259/-, (3) जमा कराने की बयाना राशी: IREPS पोर्टल पर निर्दिष्ट अनुसार (4) बिड जमा कराने एवं बिड खुलने की तिथि एवं समय: IREPS पोर्टल पर निर्दिष्ट अनुसार (5) निविदा शूल्क: IREPS पोर्टल पर निर्दिष्ट अनुसार (6) वेबसाईट विवरण एवं नोटीस बोर्ड जहाँ निविदा का विवरण देख सकते है एवं कार्यालय का पता: www.ireps.gov.in नोटीस बोर्ड एवं उप मुख्य विद्युत अभियंता (निर्माण) का कार्यालय, पश्चिम रेलवे, निर्माण भवन- असारवा, अहमदाबाद (गुजरात-382345) CPM-036

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादक: लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/ 95